मूल्य ₹20/-

खोजी एनसीआर

अक्टूबर-नवम्बर 2020

राष्ट्रीय द्विमासिक पत्रिका

बरगलाने वाली सियासत

सेना भर्ती रोहतक

19 नवंबर 2020

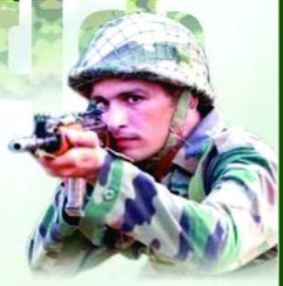

रोहतक, झज्जर, सोनीपत एवं पानीपत के युवाओं के लिए
भारतीय सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर

पद श्रेणियां

- जनरल ड्यूटी
- क्लर्क
- ट्रेड्समैन

इच्छुक युवक भारतीय सेना
की ऑफिशियल वेबसाइट
www.joinindianarmy.nic.in
पर ऑनलाइन करें आवेदन

आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2020

खोजी एनसीआर

द्विमासिक पत्रिका

अंक-02, वर्ष-01, अक्टूबर-नवम्बर 2020

पृष्ठ-32, मूल्य-20 रूपए

RNI No : HARHAIN/2015/62918

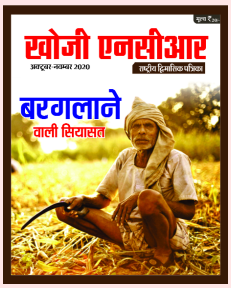

Editorial Department

Editor	Dharampal Arya
Sub Editor	Naresh Arora
Edu Reporter	D.k.Gupta
Crime Reporter	Naresh Garg

Our Writer

Dr. Yatender Garg	F.P.Jhirka
Brij Bhushan Gupta	Faridabad

Advisor

Meena Arya	Female
Naresh Singla	Education
Rajesh Chhokar	Media

Legal Advisor

Rajesh Chhokar Advocate Nuh (Haryana)

Manoj Kumar Firozpur Jhirka Nuh (Haryana)

Layout Designer

Manish Tomar

Phone N0 01268-277129,9416254840, 9518002332

E-Mail khojincr@gmail.com

Editorial Office Ward N0 4 Firozpur Jhirka Distt. Nuh Haryana

मुद्रक तथा प्रकाशक धर्मपाल आर्य द्वारा स्वास्तिका क्रिएशन, 19 डीएसआईडीसी शेड, स्कीम-3, ओखला फेस-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित करवाकर, फिरोजपुर झिरका, वार्ड नं. 4, जिला मेवात, हरियाणा से प्रकाशित किया। सभी विवादों का निपटारा फिरोजपुर झिरका न्यायालय होगा।

संपादक धर्मपाल आर्य

संपादकीय

श्रमिकों की सुध

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 पर श्रम संबंधी स्थायी समिति ने प्रवासी कामगारों के लिए एक कल्याण कोष के निर्माण की सिफारिश की है । जिस दौर में देश का मजदूर तबका सबसे ज्यादा लाचारी और जोखिम का सामना कर रहा है, उसमें उसकी अनदेखी करना एक परिपक्व और न्याय पर आधारित लोकतंत्र की पहचान नहीं हो सकती थी। इस लिहाज से देखें तो संसद की एक समिति ने देश भर में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के मद्देनजर जिन कुछ उपायों पर विचार करने का सुझाव दिया है, वे वक्त की जरूरत हैं। गौरतलब है कि संसद में पेश सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 पर श्रम संबंधी स्थायी समिति ने प्रवासी कामगारों के लिए एक कल्याण कोष के निर्माण की सिफारिश की है और इससे संबंधित संहिता में इस कोष का एक अलग श्रेणी के रूप में उल्लेख करने पर जोर दिया है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जाए; ऐसा प्रवासी जो अपने पैतृक राज्य में इसके तहत पंजीकृत नहीं हो सका है, उसे अपने डेटा को शामिल करने की सुविधा होनी चाहिए कि वह एक अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक है। निश्चित रूप से कल्याणकारी निधियों के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों या कामगारों के हित सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होना चाहिए। मगर सवाल यह है कि अलग-अलग मोर्चों पर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले कामगारों के कोई भी समूह कल्याणकारी निधियों के दायरे से बाहर कैसे रहे! इतने व्यापक तंत्र में आमतौर पर छोटी से छोटी गतिविधि भी प्रशासन की नजर में रहती है। लेकिन अब तक ऐसा ठोस तंत्र विकसित नहीं हो सका, जो प्रवासी मजदूरों से संबंधित आंकड़ों का दस्तावेजीकरण कर सके। वरना क्या वजह है कि संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार को यह कहना पड़ा कि पूर्णबंदी की वजह से अलग-अलग शहरों से घर लौटने या रास्ते में ही जान गंवा देने वाले प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जाहिर है, यह सरकार के लिए एक असुविधाजनक स्थिति है। इसलिए समिति के सुझावों के आलोक में अगर प्रवासी मजदूरों का कोई डाटाबेस तैयार होता है तो वह न केवल कल्याणकारी योजनाओं से लेकर संकटकाल में श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, बल्कि उनसे संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण में भी मददगार साबित होगा।

यह छिपा नहीं है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मार्च में जब अचानक ही पूर्णबंदी लागू कर दी गई थी, तब सबसे बड़ी त्रासदी गरीब मजदूरों के सामने ही खड़ी हो गई। एक ओर फैक्ट्रियों से लेकर निर्माण कार्यों के हर क्षेत्र में अचानक ही काम बंद हो गया और मजदूरों की रोजी-रोटी छिन गई, वहीं आमदनी के सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद उनके लिए किसी दूसरे शहर में रहना और वहां का खर्च उठाना संभव नहीं रहा। इसलिए लाखों मजदूर ट्रेन या बस जैसे कोई साधन नहीं मिलने के बावजूद पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने गांवों की ओर लौट चले। रास्ते में भूख-प्यास से लेकर जिस तरह की तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ा, उसे बयान करना मुश्किल है।

जिले के सबसे बडे गांव सिंगार का मंदिर ... पेज 11 पर

पड़ोसियों पर दादागीरी करता चीन... पेज 15 पर

फंसे कर्ज का मर्ज... पेज 19 पर

बॉलिवुड के टॉप 3 सुपरस्टार्स संग साइन ... पेज 24 पर

बरगलाने वाली सियासत

गुड़ चढ़ा कर शहर गटकाने में भारतीय नेताओं का कोई सानी नहीं। भाखड़ा बांध का यह कह कर विरोध किया गया कि सरकार किसानों को बिजली निकला हुआ थोथा पानी देगी। सूचना तकनोलोजी पर वामपंथियों ने शोर मचाया कि अब कंप्यूटर से पांच आदमियों का काम एक से लिया जाएगा जिससे चार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दोनों अफवाहें बेबुनियाद निकलीं। भाखड़ा बांध जहां उत्तर भारत के विकास का सारथी बना वहीं कंप्यूटर तकनोलोजी से रोजगार के अवसर बढ़े। इसी तरह केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार व किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए तीन अध्यादेश लाई है लेकिन विपक्ष ने न इसका विरोध किया बल्कि किसानों को बरगलाया भी जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ किसान संगठन विरोध में सड़कों पर भी उतरे हैं। उन्हें यह कह कर भरमाया जा रहा है कि इन सुधारों के बहाने सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। सच्चाई यह है कि ये कृषि उपज की बिक्री हेतु पहले की व्यवस्था के साथ-साथ एक समानांतर व्यवस्था बनाई जा रही है। यह किसानों पर निर्भर होगा कि वह किस व्यवस्था के अंतर्गत फसल बेचना चाहते हैं। नई व्यवस्था एक नया विकल्प है, जो वर्तमान मंडी व्यवस्था के साथ-साथ चलती रहेगी।

केंद्र सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में सुधार करते हुए किसानों को अधिसूचित मंडियों के अलावा भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट दी है। इस विषय में चार बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, अब किसी भी मंडी, बाजार, संग्रह केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कारखाने में फसल बेचने के लिए किसान स्वतंत्र हैं। इससे किसानों का मंडियों में होने वाला शोषण कम होगा और अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। किसानों के लिए पूरा देश एक बाजार होगा। दूसरा, अब मंडी व्यवस्था के बाहर के व्यापारियों को भी फसलों को खरीदने की अनुमति होगी। अधिक व्यापारी किसानों की फसल खरीद सकेंगे जिससे उनमें किसान को अच्छा मूल्य देने की प्रतिस्पर्धा होगी। तीसरा, मंडी के बाहर व्यापार वैध होने के कारण मंडी व्यवस्था के बाहर कृषि व्यापार और भंडारण संबंधित आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ेगा। चौथा, अब अन्य राज्यों में उपज की मांग, आपूर्ति और कीमतों का आर्थिक लाभ किसान स्वयं या किसान उत्पादक संगठन बना कर उठा सकते हैं। उन्हें खेत या घर से ही सीधे किसी भी व्यापारी को फसल बेचने का अधिकार होगा। इससे किसान का मंडी तक का भाड़ा भी बचेगा। अभी तक मंडी पहुंचने के बाद सही मूल्य न मिलने पर भी किसान फसल बेचने को मजबूर था, क्योंकि वापसी का भाड़ा देना और नुकसानदायक होता। यदि जल्द खराब होने वाली उपज हो तो मंडी पहुंचने के बाद उसे किसी भी मूल्य पर बेचने की मजबूरी होती है। इसका लाभ बिचौलिये उठाते रहे हैं। अब किसान अपने घर या खेत से उचित मूल्य मिलने पर

अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। विशेषताओं के बावजूद इन संशोधनों में सुधार की गुंजाइश भी है,

भाखड़ा बांध

जहां उत्तर भारत के विकास का सारथी बना वहीं कंप्यूटर तकनोलोजी से रोजगार के अवसर बढ़े। इसी तरह केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार व किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए तीन अध्यादेश लाई है लेकिन विपक्ष ने न इसका विरोध किया बल्कि किसानों को बरगलाया भी जा रहा है।

ही फसल बेचेगा। एक अध्यादेश बुआई से पहले किसान को फसल के तय मानकों और तय कीमत अनुसार बेचने के अनुबंध की सुविधा देता है। इससे किसान फसल तैयार होने पर सही मूल्य न मिलने के जोखिम से बच जाएंगे, दूसरे उन्हें खरीदार ढूंढ़ने के लिए कहीं जाना नहीं होगा। किसान सीधे थोक और खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों, प्रसंस्करण उद्योगों आदि के साथ उनकी आवश्यकताओं और गुणवत्ता के अनुसार फसल उगाने के अनुबंध कर सकते हैं। इससे किसानों को फसल उगाने से पहले ही सुनिश्चित दामों पर फसल का खरीदार तैयार मिलेगा। किसानों की जमीन के मालिकाना अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उसकी मर्जी के खिलाफ फसल उगाने की कोई बाध्यता भी नहीं होगी। किसान खरीदार के जोखिम पर अधिक जोखिम वाली फसलों की खेती भी कर सकता है। कृषि जिन्सों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी सुगम बनाया गया है। कृषि उत्पादों को ई-ट्रेडिंग के माध्यम से बेचने की सुविधा को बेहतर बनाया गया है। किसानों को अपनी उपज के लाभकारी मूल्य प्राप्ति हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किए गए हैं। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। किसान खरीददार के जोखिम पर अधिक जोखिम वाली फसलों की खेती भी कर सकता है। कृषि जिंसों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी सुगम बनाया जा रहा है। इसी तरह कृषि उत्पादों को ई-ट्रेडिंग के माध्यम से बेचने की सुविधा को बेहतर बनाया जा रहा है। किसानों को अपनी उपज के लाभकारी मूल्य प्राप्ति हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किए गए हैं। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। विशेषताओं के बावजूद इन संशोधनों में सुधार की गुंजाइश भी है, चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था केवल गेंहू, धान जैसी कुछ फसलों और कुछ राज्यों तक ही वास्तविक रूप से सीमित रही है अत- एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। किसानों से एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद वर्जित हो और इसके उल्लघंन पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाए। दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स के प्रावधानों में भी एकरूपता होनी चाहिए। दोनों व्यवस्थाओं का समानांतर चलना किसान हित में आवश्यक है। आश्चर्य है कि मुद्दों के अभाव में विपक्ष ने किसानों को ही अपनी राजनीति का मोहरा बना लिया जिसका नुकसान अंतत- किसान व देश को ही होगा।

बचपन और खुशहाली

निश्चित तौर पर बाल मृत्यु दर में इतने सुधार के लिए करीब तीन दशक लगना एक लंबी अवधि है, लेकिन यह भी देखना होगा कि हमारे देश के व्यापक दायरे और दूरदराज के वैसे इलाकों में भी एक बड़ी आबादी रहती है, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच अपेक्षया काफी मुश्किल रही है।

किसी भी देश की सेहत की तस्वीर का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि वहां शिशुओं और छोटे बच्चों की मृत्यु दर क्या है। इस लिहाज से देखें तो आजादी के बाद से ही भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का आंकड़ा इस कदर चिंताजनक बना रहा कि कई बार इसका सीधा असर भविष्य पर पडने के आकलन सामने आने लगे। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सुधार को लेकर सरकारों की ओर से किए जाने वाले तमाम दावों के बावजूद यह स्थिति लगातार बनी रही। लेकिन पिछले तीन दशक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर किए जाने वाले लगातार कामों का सकारात्मक नतीजा सामने आया है और अब बच्चों या फिर शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में हालत काफी सुधरी है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बाल मृत्यु दर में 1990 से 2019 के बीच काफी कमी आई है। %बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान रिपोर्ट- 2020' में बताया गया है कि 1990 में पांच साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या जहां लगभग सवा लाख थी, वहीं 2019 में यह कम होकर बावन हजार रह गई।

निश्चित तौर पर बाल मृत्यु दर में इतने सुधार के लिए करीब तीन दशक लगना एक लंबी अवधि है, लेकिन यह भी देखना होगा कि हमारे देश के व्यापक दायरे और दूरदराज के वैसे इलाकों में भी एक बड़ी आबादी रहती है, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच अपेक्षया काफी मुश्किल रही है। फिर भी, जिन सीमित संसाधनों के तहत देश के स्वास्थ्य तंत्र में सुधार लाया गया और इस तक आबादी के ज्यादातर हिस्से की पहुंच बनाई गई, उसका सीधा असर लोगों की जीवन में सेहत की स्थितियों पर पड़ा। गौरतलब है कि हाल के वर्षों तक दुनिया भर में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में भारत सबसे खराब स्थिति में था। यहां बच्चों की मृत्यु दर पूरी दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा थी। लेकिन इन दशकों के दौरान बचपन की सेहत को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियानों से एक बड़ा बदलाव यह आया कि बेहद मामूली रोगों की चपेट में आकर जहां किसी शिशु या बच्चे की जान चली जाती थी, अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते उनके जिंदा बच जाने की गुंजाइश बढ़ी है। दरअसल, अब अधिकतर प्रसव सुरक्षित तरीके से अस्पताल में होने लगे हैं, जिससे प्रसव के दौरान मौतों की तादाद घटी है। इसके अलावा, नवजात शिशुओं की देखभाल और टीकाकरण के लिए सुविधाओं का विकास किया गया है। इन वजहों से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सेहत की अफसोसजनक तस्वीर में सुधार की यह स्थिति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। मौजूदा समय में कोविड-19 महामारी से जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन्म के बाद और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की सेहत पर अचानक आई मुश्किल से निपटना कितना मुश्किल हो गया है। सामान्य स्थिति में भी पिछले कई सालों से छोटे बच्चों के इन्सेफलाइटिस या चमकी बुखार से हजारों बच्चों की मौत की खबरें बताती हैं कि अभी स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी कुछ किया जाना बाकी है। सबसे जरूरी यह है कि समाज के जिन तबकों के बच्चे आमतौर पर इस मामले में हमेशा जोखिम में रहते हैं, उसमें पोषण और सेहत के लिहाज से सुरक्षित जीवन स्थितियां मुहैया कराई जाएं। तभी प्रसव के दौरान माताओं के साथ-साथ नवजात और बाकी बच्चों की मृत्यु दर में संतोषजनक कमी लाई जा सकेगी।

सहमति से आगे

सवाल है कि विदेश मंत्रियों की बातचीत में जो पांच सूत्रीय सहमति बनी है, वह मौजूदा संकट को खत्म करने में कितनी कारगर साबित होगी। सहमति के बिंदु पढ़ने-सुनने में जितने आशावादी प्रतीत होते हैं, उनसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात उन पर ठोस अमल की है। पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर चार महीने से जारी अशांति को खत्म करने के लिए गुरुवार को मास्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में जो सहमति बनी है, उसकी सार्थकता तभी है जब चीन उस पर ईमानदारी से अमल करे। वरना दोनों देशों के बीच रिश्ते इस वक्त जितने तनावपूर्ण चल रहे हैं, उसमें हालात कब क्या मोड़ ले लें, कहा नहीं जा सकता। मास्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की ढाई घंटे से ज्यादा की बातचीत में दोनों नेता जिस पांच सूत्रीय योजना पर सहमत हुए हैं, वह शांति बहाली की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत ही नहीं, चीन भी मान रहा है कि सीमा पर बिना शांति बहाल किए बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसा वह कई बार कह भी चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ जानते-बूझते वह अब तक ऐसी चालें चलता रहा है जिससे संकट गहराता जा रहा है। सवाल है कि विदेश मंत्रियों की बातचीत में जो पांच सूत्रीय सहमति बनी है, वह मौजूदा संकट को खत्म करने में कितनी कारगर साबित होगी। सहमति के बिंदु पढ़ने-सुनने में जितने आशावादी प्रतीत होते हैं, उनसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात उन पर ठोस अमल की है। दोनों देशों ने जवानों को सीमा से तत्काल पीछे हटाने के प्रयास करने, दोनों देशों के जवानों को एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने और वास्तविक नियंत्रण रेखा के प्रबंधन संबंधी सभी मौजूदा समझौतों का पालन करने की बात कही है। इसके अलावा सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ताएं जारी रखने और भारत-चीन सीमा मामले पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद बनाए रखने सहमति बनी है। ऐसा नहीं है कि ये समझौते पहली बार हुए हैं। भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते के अनुच्छेद-6 में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के दो किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। समझौते के मुताबिक इस क्षेत्र में बंदूक, रासायनिक हथियार या विस्फोटक ले जाने की अनुमति भी नहीं है। इसके अलावा, 2013 में किए गए सीमा रक्षा सहयोग करार में साफ कहा गया था कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने-सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन चीन ने इन समझौतों का अब तक कितना पालन किया है, गलवान की घटना इसका प्रमाण है।

वह शांति बहाली की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत ही नहीं, चीन भी मान रहा है कि सीमा पर बिना शांति बहाल किए बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसा वह कई बार कह भी चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ जानते-बूझते वह अब तक ऐसी चालें चलता रहा है जिससे संकट गहराता जा रहा है।

सिमटती सिसकती नदियां

सावन तो सामान्य ही था, पर भादों जो झमक कर बरसा तो एक-एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला देश प्रकृति की इस अनमोल देन को आफत कहने लगा। घर-गांव-बस्ती पानी से लबालब हो गए। सब जानते हैं कि बरसात की ये बूंदें सारे साल के लिए अगर सहेज कर नहीं रखीं, तो सूखे की संभावना बनी रहती है। हर बूंद को सहेजने के लिए हमारे पास छोटी-बड़ी नदियों का जाल है। तपती धरती के लिए बारिश महज ठंडक नहीं लेकर आती, वह समृद्धि, संपन्नता की दस्तक भी होती है। मगर यह भी हमारे लिए चेतावनी है कि अगर बरसात औसत से ज्यादा हो गई, तो हमारी नदियों में इतनी जगह नहीं है कि वे इसके उफान को सहेज पाएं। नतीजतन, बाढ़ और तबाही के मंजर उतने ही भयावह हो सकते हैं, जितने कि पानी के लिए तड़पते बुंदेलखंड या मराठवाड़ा के। सन 2015 की मद्रास की बाढ़ बानगी है कि किस तरह शहर के बीच से बहने वाली नदियों को जब समाज ने उथला बनाया, तो पानी उनके घरों में घुस गया था। बंबई तो हर साल अपनी चार नदियों को लुप्त करने का पाप भोगती है। दूर भारत की बात क्या की जाए, राजधानी दिल्ली में यमुना नदी टनों मलबा उड़ेले जाने के कारण उथली हो गई है। एनजीटी ने दिल्ली मेट्रो सहित कई महकमों को चेताया, इसके बावजूद निर्माण से निकली मिट्टी और मलबे को यमुना नदी में खपाना आम बात हो गई है। यह सर्वविदित है कि पूरे देश में कूड़ा बढ़ रहा है और कूड़े को खपाने के स्थान सिमट रहे हैं। विडंबना है कि चलती ट्रेन की रसोई के कूड़े से लेकर स्थानीय निकाय भी अपना कूड़ा अपने शहर-गांव की नदियों में ढकेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका ही कुप्रभाव है कि नदियां मर रही और उथली हो रही हैं। नदियों के सामने खड़े हो रहे संकट ने मानवता के लिए भी चेतावनी की घंटी बजा दी है। जाहिर है कि बगैर जल के जीवन की कल्पना संभव नहीं। हमारी नदियों के सामने मूल रूप से तीन तरह के संकट हैं- पानी की कमी, मिट्टी का आधिक्य और प्रदूषण। धरती के तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते मौसम में बदलाव हो रहा है और इसी का परिणाम है कि या तो बारिश अनियमित हो रही है या फिर बेहद कम। मानसून के तीन महीनों में बमुश्किल चालीस दिन पानी बरसना या फिर एक सप्ताह में ही अंधाधुंध बारिश हो जाना या फिर बेहद कम बरसना, ये सभी परिस्थितियां नदियों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर रही हैं। बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी और ब्राह्मणी के रास्तों में पानी खूब बरसता है और इनमें न्यूनतम बहाव 4.7 लाख घनमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। वहीं कृष्णा, सिंधु, तापी, नर्मदा और गोदावरी का पथ कम वर्षा वाला है, इसलिए इसमें जल बहाव 2.6 लख घनमीटर प्रति वर्ग किमी रहता है। कावेरी, पेन्नार, माही और साबरमती में तो बहाव 0.6 लाख घनमीटर ही रह जाता है। सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए अधिक दोहन, बांध आदि के कारण नदियों के प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हुई और इसके चलते नदियों में पानी कम हो रहा है। भारतीय नदियों के मार्ग से हर साल 1645 घन किलोलीटर पानी बहता है, जो सारी दुनिया की कुल नदियों का 4.44 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था को संभालने का उचित तरीका

⏩ कृषि के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को नहीं बचा पाएंगे। छोटे उद्योगों की स्थिति भी डांवाडोल है। मार्च में इन्हें 11.49 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जो जून में 11.32 लाख करोड़ रुपये रह गया। इतना जरूर है कि अप्रैल में अधिक गिरावट आई थी, जिसकी कुछ भरपाई जून में हो गई, फिर भी मार्च की तुलना में जून में ऋण गिरा, जबकि सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये की एक योजना छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए बनाई थी।

भारत सरकार द्वारा हाल ही में कुछ और चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सही दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इस कदम से देश में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई है। इसका लाभ आने वाले समय में हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन शायद चीन तब तक नहीं मानेगा, जब तक हम उसके निर्यात पर शिकंजा नहीं कसेंगे। इस पृष्ठभूमि में हमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार का आकलन है कि अप्रैल में 75 प्रतिशत, मई में 60 प्रतिशत और जून में 40 प्रतिशत गिरावट रही, यानी इस तिमाही में गिरावट औसतन 58 प्रतिशत रही। इस अंतर का कारण यह है कि सरकार ने जीडीपी की गणना उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की है और इस समय मात्र उन्हीं बड़ी कंपनियों के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनका कारोबार लॉकडाउन के समय भी अनवरत चलता रहा है, जैसे मोबाइल फोन, बिजली आपूर्ति, ई-कॉमर्स इत्यादि से जुड़ी कंपनियां। तमाम छोटी कंपनियों ने इस तिमाही के अपने आंकड़े अब तक प्रकाशित ही नहीं किए हैं। गौरतलब है कि देश में 95 प्रतिशत रोजगार असंगठित क्षेत्र में हैं और जीडीपी में उनका योगदान 45 प्रतिशत है। असंगठित क्षेत्र के तहत हमारे छोटे विद्यालय, टेलरिंग, टैक्सी, किराना एवं डॉक्टर इत्यादि आते हैं। चूंकि इनके कारोबार में जो भारी गिरावट आई, वह उपरोक्त आंकड़ों में शामिल नहीं दिखती, इसलिए कहा जा सकता है कि ये आंकड़े जीडीपी की सही स्थिति को नहीं बताते। सरकार के अनुसार उक्त तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन अरुण कुमार के अनुसार अप्रैल में मंडियों में आवक 50 प्रतिशत रह गई थी, इसलिए तिमाही में इसका प्रभाव कम से कम 16 प्रतिशत की गिरावट का होना चाहिए। ऐसे में कृषि की जीडीपी में वृद्धि तर्कसंगत नहीं दिखती है। यदि यह मान लें कि कृषि में वास्तव में वृद्धि हुई, तो भी देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा केवल 14 प्रतिशत है। 14 प्रतिशत जीडीपी में 3.4 प्रतिशत वृद्धि का अर्थ हुआ, कुल 0.24 प्रतिशत की वृद्धि, जो कि नगण्य है। जाहिर है कि कृषि के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को नहीं बचा पाएंगे। छोटे उद्योगों की स्थिति भी डांवाडोल है। मार्च में इन्हें 11.49 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जो जून में 11.32 लाख करोड़ रुपये रह गया। इतना जरूर है कि अप्रैल में अधिक गिरावट आई थी, जिसकी कुछ भरपाई जून में हो गई, फिर भी मार्च की तुलना में जून में ऋण गिरा, जबकि सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये की एक योजना छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए बनाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस योजना का उपयोग बैंकों ने पूर्व में दिए गए ऋण को रिसाइकल करने के लिए किया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऋण में गिरावट प्रत्येक क्षेत्र में आई है। इनमें गाड़ियों पर दिए जाने वाले ऋण में सबसे कम 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। मेरे अनुमान से देश में कोरोना के इस कालखंड में रेल एवं बस सेवाएं प्रभावित होने से तमाम लोगों ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी है। लेकिन यहां पर यह भी याद रहे कि ऐसी खरीद का स्वभाव एक बार का होता है। अत- यह भी नहीं टिकेगी। प्रॉपर्टी में भी ऋण में गिरावट केवल 0.7 प्रतिशत की हुई है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसे बिल्डर हैं, जो प्रॉपर्टी के न बिकने के कारण बेहद मुश्किल में हैं और उन्होंने ऋण लिया है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की स्थिति अति-गंभीर दिखती है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का कहना है कि भारत को अपने को विश्व अर्थव्यवस्था से और कारगर रूप से जोड़ना चाहिए, निर्यात को बढ़ाना चाहिए और विदेशी पूंजी को आकर्षित करना चाहिए। लेकिन यही काम तो हम पिछले वर्षों में करते आ रहे हैं। इसके बावजूद हमारी जीडीपी लगातार गिर रही है, इसलिए हमें वैश्वीकरण से पीछे हटने पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में वैश्वीकरण की छत्रछाया में हमारे देश के अनेक उद्यमी अपनी पूंजी को बाहर ले जाने को उत्सुक हैं। यहां तक कि वे चीन जैसे देशों में भी निवेश एवं उत्पादन कर रहे हैं, जहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की छूट है, नौकरशाही भ्रष्ट है, परंतु उद्यमी से सहयोग करती है और जहां श्रम कानून ढीले हैं। देसी उद्यमी चीन में उत्पादन करके भारत को माल भेज रहे हैं। इन्हीं देसी उद्यमियों के चलते आज हमारे देसी उद्योग चरमरा रहे हैं। एक उदाहरण पर गौर करें। भारत सरकार ने करोड़ों एलईडी बल्ब सप्लाई करने का ठेका जिस कंपनी को दिया था, उसने ये बल्ब चीन में बनाकर भारत सरकार को उपलब्ध कराए। यदि इन पर आयात कर ज्यादा होता तो उक्त कंपनी भारत में ही इन बल्बों का उत्पादन करती। विकल्प यह है कि हम आयात कर में भारी वृद्धि करें। इसका परिणाम यह होगा कि विदेशों में बना माल अपने देश में प्रवेश नहीं करेगा और मांग की पूर्ति के लिए देश में उत्पादन अनिवार्य हो जाएगा। इससे देश में उत्पादन बढ़ेगा। उस उत्पादन के रोजगार भी बढ़ेंगे। रोजगार के चलते लोगों में जो क्रयशक्ति आएगी, उससे बाजार में मांग बढ़ेगी और चीन में माल बनाकर भारत भेजने वाली कंपनियों के लिए देश में निवेश करना लाभप्रद हो जाएगा। लिहाजा सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की गुमराह करने वाली सलाह से बचना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि उद्यमी की दृष्टि तो धन कमाने पर टिकी होती है। यदि उद्यमी के लिए चीन में उत्पादन करके भारत में माल को सप्लाई करना लाभप्रद है, तो वह भारत में उत्पादन नहीं करेगा।

ऐसे में सरकार को चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए आयात कर में भारी वृद्धि करे, विदेशी पूंजी के पीछे भागने के स्थान पर देश की पूंजी को अपने ही देश में निवेश के लिए प्रेरित करे और निवेशकों को नौकरशाही की वसूली से राहत दे। यह सब करने पर जीडीपी अपने आप उठने लग जाएगी। चीन पर सीधे नकेल कसने की एक सीमा है। आज की आवश्यकता यह है कि सरकार उन देसी उद्यमियों पर नकेल कसे, जो विदेश में निवेश कर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

क्या किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण दो बार हो सकता है ?

अभी तक वैज्ञानिकों में धारणा रही है कि एक बार किसी को अगर कोरोना संक्रमण हो जाता है और उसके शरीर में इसके लिए एंटीबॉडी के लिए एंटीजेन बन जाते हैं तो उसके ठीक हो जाने के बाद भी ये शरीर में लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। क्या किसी व्यक्ति को दुबारा कोविड-19 हो सकता है ? कोरोना वायरस की यह पहेली इस समय दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इस समय जब यह लग रहा है कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन के बहुत करीब पहुँचने वाले हैं तो ऐसे सवाल यह भी बता रहे हैं कि हम अभी तक कोरोना वायरस की सभी पहेलियों को सुलझा नहीं सके हैं और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इससे कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है?

पिछले दिनों हांगकांग से एक व्यक्ति को दुबारा कोविड-19 होने की खबर आई थी। इसके साथ ही बेल्जियम और नीदरलैंड में भी ऐसे एक-एक मामले पता पड़े। शनिवार को जब अपने देश के बैंगलुरू में भी ऐसे ही एक मामले का पता पड़ा तो इसी के साथ यह खबर भी आई कि ऐसे ही एक मामला मामला मुंबई में भी दर्ज हुआ है। हांगकांग को छोड़कर अभी बाकी मामलों का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है। हांगकांग वाले मामले का न सिर्फ पूरा वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है बल्कि यह अध्ययन एक मेडिकल रिसर्च जरनल में प्रकाशित भी हो चुका है। हांगकांग में इस व्यक्ति को पहले कोरोना संक्रमण हुआ था और उसके लक्षण भी उस पर दिखाई पड़े थे। बाद में वह ठीक हो गया और वह कोरोना नेगेटिव भी पाया गया। कुछ दिन बाद जब एक बार फिर उसकी जांच हुई तो वह पॉज़िटिव पाया गया, हालांकि इस बार कोविड-19 रोग का कोई लक्षण उसमें नहीं दिखाई दिया था। अभी तक वैज्ञानिकों में धारणा रही है कि एक बार किसी को अगर कोरोना संक्रमण हो जाता है और उसके शरीर में इसके लिए एंटीबॉडी के लिए एंटीजेन बन जाते हैं तो उसके ठीक हो जाने के बाद भी ये शरीर में लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। यानि अगर दुबारा वह व्यक्ति वायरस के संपर्क में आता है तो संक्रमण सफल नहीं हो सकेगा। अब जब दुबारा संक्रमित होने के मामले मिलने लगे हैं तो इसका अर्थ क्या यह मान लिया जाए कि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार से अधिक हो सकता है?

एक बार किसी को अगर कोरोना संक्रमण हो जाता है और उसके शरीर में इसके लिए एंटीबॉडी के लिए एंटीजेन बन जाते हैं तो उसके ठीक हो जाने के बाद भी ये शरीर में लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। यानि अगर दुबारा वह व्यक्ति वायरस के संपर्क में आता है तो संक्रमण सफल नहीं हो सकेगा। अब जब दुबारा संक्रमित होने के मामले मिलने लगे हैं तो इसका अर्थ क्या यह मान लिया जाए कि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार से अधिक हो सकता है?

कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन यह खतरा बहुत बड़ा नहीं है, कम से कम अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा। इसे हांगकांग के मामले से समझा जा सकता है। वह व्यक्ति एक बार संक्रमण के बाद उससे मुक्त हो गया। पहली बार संक्रमण ने उसे परेशान किया, लेकिन दूसरी बार जब संक्रमण हुआ तो उसमें कोई लक्षण नहीं थे, यानी उसे इसका पता भी नहीं पड़ा था। जाहिर है कि जब वह दुबारा वायरस के संपर्क में आया तो इसके पहले कि वायरस उसके लिए कोई परेशानी खड़ी करता उसके शरीर के एंटीबॉडी और एंटीजेन सक्रिय हो गए। दरअसल अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें पहली बार भी वायरस के लक्षण दिखे हों और दूसरी बार भी उसके लक्षण दिखाई दिए हों। अगर ऐसा होता है तो सचमुच परेशानी खड़ी हो सकती है। वायरस के मामले में आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब दो संक्रमण के बीच वायरस में म्युटेशन हो जाए और वह अपना रूप बदल दे। जैसा कि जुकाम वगैरह के वायरस के साथ होता है जो लगातार अपना रूप बदलता रहता है। इसलिए हमें एक ही मौसम में एक से ज्यादा बार जुकाम हो सकता है। यह भी सच है कि अभी तक हम कोविड-19 वाले कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह से कुछ नहीं जानते। हमें अभी तक नहीं पता कि उसमें कितना म्यूटेशन हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों ने म्यूटेशन की बात तो कही है लेकिन अभी तक इसके पक्के प्रमाण नहीं मिल सके हैं। ऐसे म्यूटेशन के तो नहीं ही मिले हैं जिससे दुबारा संक्रमण हो सके। यह भी सच है कि दुबारा संक्रमण के अभी तक इक्का दुक्का मामले ही सामने आए हैं। अभी तक पूरी दुनिया में कोविड-19 संक्रमण के 2.73 करोड़ मामले दर्ज हुए हैं जिसमें 1.94 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। उस हिसाब से देखें तो दुबारा संक्रमण के मामलों की संख्या बहुत कम है, बल्कि लगभग नगण्य है। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा रहा है कि बहुत कम या शायद अपवाद स्वरूप मामलों में ही दुबारा संक्रमण होने का खतरा है। इसमें भी कुछ वैज्ञानिकों को आशंका है कि दुबारा जांच के समय पहले संक्रमण के बचे हुए निष्क्रिय वायरस से भी पॉज़िटिव नतीजे आ सकते हैं। जाहिर है कि कोविड-19 के दुबारा संक्रमण का मामला ऐसा नहीं है कि उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हुआ जाए।

लाचार भारत को देखा है

विकासशील का तगमा लगे भारत को
कभी धूम मचाते सबने देखा है।
अनगिनत संघर्षो की राहों पर प्यारे
हमने दीवानों को खून बहाते देखा है।
आजादी की चाह मन में पालो को
हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ते देखा है।
आजादी के बाद पलायन का बुरा दौर
जो दो देशों में हमने देखा था,
आज फिर एक बार देश ने
उस लाचार भारत को देखा है।
गर्म धूप में नंगे पाव चलते हुए
उनके पैरों में छालों को हमने देखा है।
दिशाहीन सड़कों पर चलते-चलते
उस अभागिन महिला को सरे राह
सड़क पर बच्चा पैदा करते देखा है।
भूखे व प्यासे बेबस लोग बेचारे
बच्चों का भार भी न उठा सके जो,
इन्हीं सड़कों पर उन अभागों को
अटैची पर सोते बच्चे ले जाते देखा है।
अबला समझे जाने वाली वीर बालिका को
साइकिल पर बैठ बीमार पित संग
तेज धूप में मीलों लम्बा सफर करते
मजबूरी में पैडल मारते देखा है।
इसे विडम्बना कहें या शासन की प्रताड़ना
लाशों के ढेरों के साथ बैठकर
उन बेबेसों को ट्रकों में जाते हुए देखा है।
भूख काटने को दौड़ रही थी
रोटी की कोई आस नहीं थी
पापी पेट की खातिर, मरे हुए कुत्ते को
खाकर भूख मिटाते देखा है।
जिस भारत की कभी कल्पना भी न थी
उसे रह-रहकर यूं घुटते हुए देखा है।

फिर आई बरसात

(बाल गीत)

लो फिर देखो वर्षा आई
चहुंओर है खुशियां छाई।
भीगे-भीगे है सब नर नारी
नहाने की सब कर रहे तैयारी।
रिम झिम बादल बरस रहे हैं
पानी को पक्षी तरस रहे हैं।
हो गई पूरी सबकी मानो मुराद
उछल रहे होकर सब आजाद।
बरसात देख गुन्नू का मन डोला
मैं भी नहाऊंगा मुख से ये बोला।
कितना अच्छा पानी बरस रहा है
नहाने को मेरा मन मचल रहा है।
वर्षा में खूब नहाऊंगा मैं अब
नोनी, कुहू जी, तुम आओगे कब।
मिलकर खून नहाएंगे हम
मौज मस्ती खूब मनाएंगे हम।
वर्षा रानी कल भी आना
कल भी हमने खूब नहाना।

कैसे कैसे बोल

कुछ प्राणियों की मनोवृत्ति भैया
हर किसी को समझ नहीं आती है
उन्हें कहां पर बोलना होता है
और कहां पर बोल जाते है
इतना ही नहीं,
जहां पर खामोश रहना है
वहां पर मुंह खोल जाते है।
कटे जब शीश सैनिक का
तो वो खामोश रहते है
कट जाए अगर एक सीन पिक्चर का
तो सारे बोल जाते है।
आज के ये प्यारे बच्चे
जमाने भर की सुनते है
अगर मां-बाप कुछ बोले
तो जवाब में बच्चे बोल जाते है।
यूं तो बनाते है रिश्ते
जमाने भर से अक्सर हम
मगर घर में जरूरत हो
तो रिश्ते भूल जाते है।
हवाओ की तबाही को वे
सभी चुपचाप सहते रहते है।
चिरागों से जब हुई गलती
तो सारे बोल जाते है।

जिले के सबसे बडे गांव सिंगार का ऐतिहासिक राधा- कृष्ण मंदिर

कोजिले के सबसे बडे गांव सिंगार का ऐतिहासिक राधा- कृष्ण मंदिर इन दिनों श्रदा का केंद्र बना हुआ है। सावन मास के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावडा लगा हुआ है। मंदिर में गांव सहित आस-पास क्षेत्र के लोग सावन के महीने में मंदिर में भगवान शिव को पूजने के लिए पहुंचते हैं।

ऐसे पहुंचे मंदिर :- होडल-नगीना रोड पर सिंगार गांव स्थित राधा- कृष्ण मंदिर में गांव के अड्डे से रिकशा लेकर या फिर पैदल मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अपने वाहन से जाना हो तो गांव से होडल-नगीना रोड से मुड कर लफूरी की तरफ जाने वाली सड़क से मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

तैयारियां :- सावन के लिए राधा- कृष्ण के मंदिर की सुंदर फुलों से सजावट की गई है। रंग-बिरंगी रोशनी वाली लाईटों से मंदिर को नहाया गया है। सावन में मंदिर में पूरे दिन भजन-कीर्तन के साथ रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने घर जाते हैं।

मंदिर का इतिहास :- बृज के छोर पर बसे इस गांव में द्वापर युग में रासलीला के दौरान कभी यहां के तालाब में भगवान श्री कृष्ण नहा कर अपना श्रंगार किया था। तभी से ही गांव वालों ने तालाब के पास एक मंदिर बनाकर गांव का सिंगार रख दिया। गांव में कृष्ण जी ने श्रंगार के साथ-साथ एक स्थान पर घंटी भी बजाई थी। जिससे उस स्थान का नाम ताली रख दिया व मुंह धोने वाले तालाब का नाम मुंहखर रख दिया। ये मंदिर व स्थान गांव में आज भी मौजूद हैं। क्षेत्र के आसपास के लोगों द्वारा इन स्थनों की विशेष पूजा की जाती है। आज मंदिर में माता दुर्गा के अलावा शिव परिवार, राम भक्त हनुमान जी, राधा-कृष्ण,लक्ष्मी-गणेश जी की प्रतिमा भी विराजी गई हैं।

मंदिर की विशेषता :-भगवान श्री कृष्ण द्वारा यहां पर श्रंगार करने के बाद गांव का नाम सिंगार रखने के साथ ही यहां पर मंदिर बनवाया गया था। भगवान श्री कृष्ण के कदम पडने के बाद बनाया गया मंदिर अपने आप में ही विशेष है। मंदिर के तीनों ओर तालाब बना हुआ है। सावन में मंदिर परिशर हमेशा गुलजार रहता है। सावन के पवित्र महीने में यत्नपूर्वक शिवपूजन किया जाए तो भगवान शिव सभी प्राणियों की रक्षा करती हैं। देश के विभिन्न भागों की पूजनम्पराओं, पद्धतियों एवं उत्सव मनाने के रीति-रिवाजों में भले ही कुछ अंतर हो,किंतु नियम संयम से व्रत रखकर सात्विक भावना से श्रद्धापूर्वक शिव की अराधना करने का विधान सभी जगह एक ही समान ही देखने को मिलता है।

व्रत त्यौहार

- बुधवार 2 अक्टूबर - महात्मा गाँधी जयन्ती एवं मासिक विनायक चतुर्थी,
- गुरुवार 3 अक्टूबर - बिल्व निमन्त्रण, स्कन्द षष्ठी पूजा
- शुक्रवार 4 अक्टूबर - सरस्वती आवाहन, कल्पारम्भ, अकाल बोधन
- शनिवार 5 अक्टूबर- सरस्वती पूजा, नवपत्रिका पूजा छठ पूजा व मेला (जयपूर)
- रविवार 6 अक्टूबर - सरस्वती बलिदान, दुर्गा अष्टमी, सन्धि पूजा, वीरांगना रानी दुर्गावती जयंती
- सोमवार 7 अक्टूबर- दुर्गा बलिदान, सरस्वती विसर्जन, आयुध पूजा, बंगाल महानवमी, बुद्ध जयन्ती
- मंगलवार 8 अक्टूबर- दुर्गा विसर्जन, दशहरा, विजयदशमी विद्याआरम्भम् का दिन, मध्वाचार्य जयन्ती, श्री हरी जयंती
- बुधवार 9 अक्टूबर- पापांकुशा एकादशी, पंचक प्रारंभ
  घर में है परेशानी तो महिलाएं नवदुर्गा में जरूर करे यह उपाय, खुशियां देने लगेगी घर में दस्तक
- गुरुवार 10 अक्टूबर- पद्मनाभ द्वादशी
- शुक्रवार 11 अक्टूबर- प्रदोष व्रत
- रविवार 13 अक्टूबर- शरद पूर्णिमा, कोजागर पूजा, वाल्मीकि जयन्ती, मीराबाई जयन्ती

नवंबर 2019 के व्रत, पर्व और त्यौहार-

- 1 नवंबर दिन शुक्रवार को लाभ पञ्चमी है।-
- 2 नवंबर दिन शनिवार को छठ पर्व पूजा मनाया जायेगा।
- 3 नवंबर दिन रविवार को भानु सप्तमी है एवं अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ होगा।
- 4 नवंबर दिन सोमवार को गोपाष्टमी एवं मासिक दुर्गाष्टमी है।
- 5 नवम्बर दिन मंगलवार को अक्षय नवमी एवं जगद्धात्री पूजा है।
- 7 नवंबर दिन गुरुवार को भगवान श्रीकृष्ण ने कंस का वध किया था।
- 8 नवंबर दिन शुक्रवार को देव उठनी ग्यारस (एकादशी) पर्व, तुलसी विवाह है, इस दिन भीष्म पञ्चक भी प्रारम्भ होगा। योगेश्वर द्वादशी भी इसी दिन लग जाएगी। इस दिन नामदेव जयंती भी है।
- 9 नवंबर दिन शनिवार को, प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी एवं कालिदास जयंती है।
- 10 नवंबर रविवार को बैकुण्ठ चतुर्दशी, विश्वेश्वर व्रत, मिलाद उन-नबी, ईद-ए-मिलाद है।
- 11 नवंबर दिन सोमवार को मणिकर्णिका स्नान, चौमासी चौदस
- 12 नवंबर दिन मंगलवार को देव दीवाली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयन्ती है, भीष्म पञ्चक भी समाप्त हो जाएगा।
- 13 नवंबर दिन बुधवार को मार्गशीर्ष मास प्रारम्भ होगा, (उत्तर), मासिक कार्तिगाई भी है।
- 14 नवंबर दिन गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू जयन्ती (बाल दिवस) एवं रोहिणी व्रत है।

2020

के कोरोना काल में निश्चित रूप से सिजेरियन डिलीवरी में काफी कमी आई है

कोरोना का सकारात्मक साइड इफेक्ट माना जा सकता है कि सिजेरियन में 61 से 91 प्रतिशत कमी के साथ अब सामान्य डिलीवरी होने लगी है। पुणे के मेडीकेयर हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट डॉ. गणेश राख का कहना है कि यह सरकारों के लिए भी सोचने की बात है कि अब ऐसा क्या हो गया कि ज्यादातर बच्चे सामान्य डिलीवरी से होने लगे हैं।

लॉकडाउन में सिजेरियन डिलीवरी में भारी कमी

सामान्य प्रसव के मामले बढ़े

परिस्थितियां कैसे बदलती हैं इसका जीता-जागता उदाहरण चिकित्सालयों में सिजेरियन डिलीवरी के तेजी से घटते आंकड़ों से समझा जा सकता है। लॉकडाउन के पहले सिजेरियन डिलीवरी आम होती जा रही थी और खासतौर से निजी चिकित्सालयों में सिजेरियन डिलीवरी का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाली स्थिति में रहा है। पर कोरोना के चलते सिजेरियन डिलीवरी का स्थान सामान्य डिलीवरी ने ले लिया है। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में 64 से 91 प्रतिशत सिजेरियन डिलेवरी में कमी आई है। हो सकता है कि यह आंकड़े कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण हों पर इससे नकारा नहीं जा सकता कि 2020 के कोरोना काल में निश्चित रूप से सिजेरियन डिलीवरी में काफी कमी आई है। सिजेरियन डिलीवरी तो एक उदाहरण है, तथ्य तो यह बता रहे हैं कि अन्य बीमारियों के इलाज में भी कमी आई है। दवाओं की मांग कम हुई है तो अस्पतालों में होने वाली बेतहाशा भीड़ में भी जबरदस्त कमी आई है। कोरोना ने छोटी-छोटी बीमारियों यहां तक कि छींक आने पर ही डॉक्टरों के चक्कर लगाने और मेडिकल जांचों के चक्रव्यूह से बड़ी राहत दी है। जहां तक डिलीवरी का प्रश्न है विशेषज्ञों का मानना है कि सिजेरियन डिलीवरी अंतिम विकल्प के रूप में या अति जटिलता की स्थिति में ही होनी चाहिए पर पिछले कुछ सालों में सिजेरियन डिलीवरी का चलन-सा देखने को मिला है। अब इसे चिकित्सकीय नैतिकता के दायरे में समझने की कोशिश की जाए या सामान्य नैतिकता के दायरे में, दोनों ही दृष्टि से गैरजरूरी सिजेरियन डिलीवरी को उचित नहीं माना जा सकता। विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े हो सकता है अतिश्योक्तिपूर्ण हैं पर हैं वास्तव में यह चिंतनीय। पिछले साल टू मच केयर अभियान के तहत आईआईएम अहमदाबाद द्वारा देश भर में प्रसूति पर किए गए अध्ययन ने इस ओर खासतौर से ध्यान दिलाया गया है। देखा गया है कि निजी चिकित्सालयों द्वारा सब कुछ ठीक होने के बावजूद प्रायः सी-सेक्शन को प्राथमिकता दी जाने लगी। यह सब तो तब है जब चिकित्सक इस बात को भलीभांति जानते हैं कि सी-सेक्शन के कारण मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह तथ्य भी उभर कर आया है कि सरकारी चिकित्सा केंद्रों की तुलना में निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी का आंकड़ा लगभग उलट रहा है। जहां एक ओर सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव का आंकड़ा काफी कम है वहीं निजी अस्पतालों में यह आंकड़ा सरकारी से कई गुणा अधिक है। मजे की बात यह है कि चिकित्सालयों द्वारा प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक प्रेगनेंट महिला को परीक्षण में रखा जाता है, आए दिन सोनोग्राफी व अन्य जांचें होती हैं और अधिकांश मामलों में डिलीवरी के ठीक पहले तक निजी चिकित्सालयों द्वारा यही कहा जाता है कि सब कुछ सामान्य है और फिर डिलीवरी के लिए चिकित्सालय में लेकर जाते ही पता नहीं कैसे सब कुछ असामान्य हो जाता है। सामान्य डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी के चार्जेज में अंतर होने के कारण कहीं पैसे का मोह तो इसका कारण नहीं बनता जा रहा है। पर कोरोना ने स्थितियां बदली हैं। मुंबई के सायन हॉस्पिटल के डीन डॉ. भारमल का कहना है कि ''प्रसूती के दौरान दस से पन्द्रह प्रतिशत को ही सर्जरी की जरूरत होती है।'' पर जबसे पांच सितारा सुविधायुक्त अस्पतालों की बाढ़ आई है और जिस तरह से कैशलेस इंश्योरेंस का चलन चला है तबसे सिजेरियन डिलीवरी में तेजी से इजाफा हुआ है। यह तो कोरोना की मार, लॉकडाउन का दौर और उसके बाद भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सिजेरियन डिलीवरी की रिस्क अस्पताल और प्रसूताएं दोनों ही लेने को तैयार नहीं हैं यही कारण है कि कोरोना के कारण महिलाओं और नवजात बच्चों को बड़ी राहत इस मायने में मिली है कि सिजेरियन के कारण मां और बच्चा दोनों को ही तकलीफ होती है। जटिलताओं की भी संभावना रहती है। इसे कोरोना का सकारात्मक साइड इफेक्ट माना जा सकता है कि सिजेरियन में 61 से 91 प्रतिशत कमी के साथ अब सामान्य डिलीवरी होने लगी है। पुणे के मेडीकेयर हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट डॉ. गणेश राख का कहना है कि यह सरकारों के लिए भी सोचने की बात है कि अब ऐसा क्या हो गया कि ज्यादातर बच्चे सामान्य डिलीवरी से होने लगे हैं। उनका मानना है कि लगभग 90 प्रतिशत मामलों में सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता ही नहीं होती। यह वास्तविकता दर्शाने वाली सच्चाई है। इसे स्वीकारना होगा।आज से पाच-छह दशक पहले स्थितियां बदली हुई थीं। डॉक्टर सबसे पहले नब्ज टटोल कर, जीभ देखकर, पेट दबाकर, सिर छू कर, आंखों के नीचले हिस्से को देखकर ही बीमारी की पहचान करते थे और दो तीन दिन में दवा का फायदा नहीं होता था तब ही अन्य जांच का विकल्प होता था पर आज तो दवा बाद में पहले जांच होती है। इसी तरह सिजेरियन डिलीवरी का सिलसिला चला पर लगता है अब स्थितियां सुधरेंगी। कोरोना लॉकडाउन के कारण जिस तरह से सिजेरियन डिलीवरी में अच्छी खासी कमी आई है इसे शुभ संकेत ही समझा जाना चाहिए। आखिर प्रकृति को अपनी तरह से काम करने दिया जाना चाहिए। प्रकृति भी सामान्य प्रसव की और ही इंगित करती है।

साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे

पढ़े-लिखे लोग भी आसानी से बन रहे हैं शिकार

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाये गये लॉकडाउन के दौरान देशभर में साइबर ठगी के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के दशवतपुर गांव में साइबर ठगों ने एटीएम पिन एवं मोबाइल नंबर मांगकर दो लोगों को ठगी का शिकार बनाया। लॉकडाउन में साइबर ठग फर्जी शॉपिंग वेब बनाकर सैनेटाइजर, कोरोना सेव किट, फेस मास्क पर भारी डिस्काउंट ऑफर देकर ग्राहकों की बैंक डिटेल्स प्राप्त कर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। साइबर ठगी की घटनाओं को देखते हुए एवं लोगों के बचाव को ध्यान में रखकर बरेली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र साइबर सेल के अनुसार, लोगों के मोबाइल और ईमेल पर एक लिंक भेजकर उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। उस लिंक पर क्लिक करते ही लोगों के बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स उन लोगों तक पहुंच रही है, जो ठगी के षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के सीकर जिले में प्रसिद्ध कस्बे खाटूश्यामजी की श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा वाट्सएप पर लेटर के जरिए सहायता राशि पेटीएम अकाउंट में भिजवाने की मांग की गई है, जिसको लेकर 17 लोगों ने शिकायत दर्ज की है। इस तरह की शिकायतें दिल्ली व कोलकाता में भी दर्ज हुई हैं। अकेले राजस्थान में 200 से अधिक ठगी की शिकायत से जुड़े मामले दर्ज किये जा चुके हैं, जिसमें पीएम केयर के नाम पर 2.39 करोड़ रुपए और एक समान मासिक किश्त माफी के नाम पर 7 करोड़ रुपए का धोखा हुआ है। साइबर ठग अपनी आवाज और नाम बदलकर खाताधारकों को बैंक बंद होने व एटीएम कार्ड ब्लॉक होने के नाम का झांसा देकर उनकी गोपनीय जानकारी सेंधकर साइबर क्राइम को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। वहीं मुफ्त डॉटा, घर बैठे नौकरी और मेडिकल उपकरण का लालच देकर भी साइबर ठग लोगों को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। शातिर साइबर ठग फ्री रिचार्ज, कोरोना उपचार के लिंक व सरकारी कार्मिक वेतन में लाभ दिलवाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। फिशिंग ईमेल के जरिए नौकरी और लॉटरी का लालच देकर भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इस स्थिति में इंटरनेट पर हैकरों से बचकर काम करना जटिल बनता जा रहा है। दरअसल, साइबर ठगों के बहलाने, फुसलाने, डराने और ललचाने से न केवल अनपढ़ बल्कि कमोबेश पढ़े लिखे भी इनके जाल से स्वयं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले इन ठगों का मकसद किसी भी तरह से लोगों की बैंक डिटेल्स हथियाना है इसलिए ये पूरी प्लानिंग के साथ अपने काम अंजाम देते हैं, ताकि लोग इनके वास्तविक रूप को पहचान नहीं पाए। उल्लेखनीय है कि बढ़ती डिजिटल संस्कृति के साथ साइबर अटैक एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। विश्वभर में साइबर अटैक झेलने वाले देशों की सूची में भारत 21वें पायदान पर है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2011 से 2014 तक पंजीकृत साइबर अपराध के मामलों में लगभग 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साइबर सुरक्षा कंपनी एफ़-सिक्योर के अनुसार, जनवरी से जून 2018 तक करीब 4.36 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जिसमे सबसे अधिक अटैक रूस, अमेरिका, चीन और नीदरलैंड जैसे देशों की तरफ से किए गए। इस समय भारत की तरफ से किए गए साइबर अटैक झेलने वाले टॉप 5 देश ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, ब्रिटेन, जापान और यूक्रेन हैं।

> विमुद्रीकरण और नकदी रहित अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक साइबर सुरक्षा पर अवलंबित होगी। अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा।

साइबर और कानून विशेषज्ञों के अनुसार, घर पर ऑफिस का काम करने के दौरान डाटा लीक होने की आशंका रहती है तथा ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। साथ ही साइबर ठगी के मामले अदालतों में पहुंचने पर अधिक समय बर्बाद होगा। इन दिनों लॉकडाउन में देशभर के सभी कर्मचारी घर पर रहकर ही अपने काम कर रहे हैं। आवश्यकता है कि साइबर क्राइम के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाएं। निजी एवं गोपनीय जानकारी के अनावश्यक रूप से प्रचार-प्रसार पर रोक को लेकर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। भारत में साइबर ठगी के खिलाफ एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ तंत्र विकसित करने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

पड़ोसियों पर दादागीरी करता चीन

दक्षिण चीन सागर से लेकर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में चीन का विस्तारवाद तेज हो गया है। कोरोना महामारी के दौर में चीन भारत के लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका है। लेकिन इस आपदा काल में चीन के निशाने पर दूसरे पड़ोसी दोस्त भी हैं। चीन ताजिकिस्तान के पामीर क्षेत्र और नेपाल के एवरेस्ट को भी अपना बता रहा है। उसकी इस विस्तारवादी नीति का शिकार बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल देश भी हो रहे है। इस परियोजना के जाल में फंसे पड़ोसी देशों के इलाकों पर चीन की नजर है। ताजा मामला ताजिकिस्तान का है। चीनी सरकार की एक वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में चीन के एक इतिहासकार ने दावा किया है कि ताजिकिस्तान का पूरा पामीर क्षेत्र चीन का है, जिसे उन्नीसवीं सदी में चीन से छीना गया था। ब्रिटेन और रूस के दबाव में पामीर का क्षेत्र चीन के हाथ से निकल गया था। इतिहासकार के अनुसार ताजिकिस्तान से पामीर का इलाका वापस लिया जाना चाहिए। हाल में चीन ने एवरेस्ट को लेकर फिर विवाद खड़ा कर दिया और माउंट एवरेस्ट को चीन के तिब्बत स्वाययत क्षेत्र का हिस्सा बताया। कोरोना आपदा काल में ही चीन ने भूटान के सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य को विवादित बताया है। चीन इसे भी अपना इलाका बता रहा है। माउंट एवरेस्ट पर चीन की नजर पचास के दशक से ही है। माओत्से तुंग के कार्यकाल में भी नेपाल और चीन के बीच हुए सीमा विवाद में एवरेस्ट का मामला उठा था। लेकिन तब चीन ने एवरेस्ट को नेपाल का हिस्सा मान लिया था, कारण जो भी रहे हों। पर इस साल मई में चीन के सरकारी टेलीविजन ने एवरेस्ट को तिब्बत का हिस्सा बता कर नेपाल की नींद उड़ा दी। चीन की तरफ से ये शरारत तब की गई जब नेपाल की सत्ता में चीन के कट्टर समर्थक लोग काबिज हैं। नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन-नेपाल संबंधों को नई ऊंचाई देने का दावा कर रहे है। दिलचस्प बात तो यह है कि नेपाल का सर्वे विभाग भी स्वीकार कर रहा है कि चीन लगातार नेपाली इलाकों में घुसपैठ कर रहा है और नेपाल की जमीन हथिया रहा है। सर्वे विभाग ने पिछले साल जानकारी दी थी कि नेपाल-तिब्बत सीमा पर नेपाल के चार जिलों की छत्तीस हेक्टेयर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा सैकड़ों हेक्टेयर और जमीन पर भी चीन कब्जा करने की ताक में है। इसके बावजूद नेपाल के प्रधानमंत्री ओली चीन के खिलाफ कुछ बोलने के बजाए भारत के साथ सीमा विवाद में उलझ गए। नेपाल ने नया राजनीतिक मानचित्र तक जारी कर दिया, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्र को अपना बताया है। अब बात करें ताजिकिस्तान की। पूरे पामीर क्षेत्र पर चीन की दावेदारी का मतलब है कि उसकी नजर ताजिकिस्तान के पैंतालीस फीसद इलाके पर है। हालांकि चीन और ताजिकिस्तान के बीच सीमा विवाद 2010 में ही सुलझ गया था और समझौता हो गया था। इस समझौते के तहत ताजिकिस्तान ने पामीर का लगभग 1158 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन को 2011 में दे दिया था। उस समय चीन ने कहा था कि ताजिकिस्तान के साथ उसका सीमा विवाद खत्म हो गया है। लेकिन चीन अब फिर से नए पैंतरे चल रहा है। नेपाल पर नजर डालें तो पाएंगे कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से नेपाल भारत के नजदीक है। इसके बावजूद नेपाल ने हाल के वर्षों में चीन से खूब नजदीकियां बढ़ाई हैं। बीते वर्ष अक्तूबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काठमांडो के दौरे पर गए थे। उनका स्वागत करते हुए नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा था कि नेपाल और चीन का संबंध समुद्र की तरह गहरा और एवरेस्ट की तरह ऊंचा है। लेकिन जिस एवरेस्ट की ऊंचाई से नेपाल और चीन के संबंधों की तुलना विद्या देवी भंडारी कर रही थी, उस एवरेस्ट को चीन अपना हिस्सा बताने में लग गया है। चीन के साथ संबंधों को इस तरह परिभाषित करने का काम पाकिस्तान के हुक्मरान भी करते रहे हैं और अक्सर बताते रहे हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान का संबंध शहद की तरह मीठा, समुद्र की तरह गहरा और हिमालय की तरह ऊंचा है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड के शुरुआती भागीदारों में ताजिकिस्तान का नाम भी आता है। नेपाल भी इस परियोजना में शामिल है। दोनों देश इस परियोजनाओं से जुड़े कई समझौते कर चुके है। तजाकिस्तान में तो इससे जुड़ी कई परियोजनाओं का काम भी पूरा हो चुका है। नेपाल में भी नौ परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन चीन की गतिविधियों से अब

चीन की विस्तारवादी नीति ब्रिक्स और एससीओ के हित में नहीं है। हालांकि रूस और चीन के बीच आपसी आपसी संबंध अच्छे हैं। चीन रूस से बड़े पैमाने पर गैस खरीद रहा है, रूस उसे एस-400 मिसाइलें भी बेच रहा है। इसके बावजूद रूस चीन की विस्तारवादी नीति को पसंद नहीं कर रहा है।

नेपाल और ताजिकिस्तान की चिंता भी बढ़ने लगी है। दोनों देश इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं वे चीन के कर्ज जाल में तो नहीं फंस जाएंगे। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि चीन नेपाल और तजाकिस्तान जैसे गरीब देशों की हालत श्रीलंका जैसी कर देगा। मालूम हो कि श्रीलंका चीन के भारी कर्ज जाल में फंस चुका है। अगर नेपाल और ताजिकिस्तान जैसे देश भविष्य में चीन का कर्ज नहीं लौटा पाए तो चीन इन देशों के संसाधनों का मनमाने तरीके से दोहन करेगा। मध्य एशिया में चीन के विस्तारवादी रवैये से रूस सतर्क है। मध्य एशिया के देश एक समय में सोवियत संघ के हिस्सा रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन ने मध्य एशिया के देशों के साथ सीमा विवाद हल किया। लेकिन एक बार फिर चीन ने ताजिकिस्तान के इलाके पर दावा ठोका है। रूस को अच्छी तरह से पता है कि चीन मध्य एशिया के देशों में बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत भारी निवेश कर चुका है। आज नहीं तो कल, चीन गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाएगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि रूस मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक अपने वर्चस्व को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगा। रूस को वर्तमान भू-राजनीति में पश्चिम और मध्य एशिया में अमेरिका से नहीं, बल्कि चीन से चुनौती मिलेगी।

महिला सबलीकरण की हकीकत

स्त्री को अपने किसी भी अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष क्यों करना पड़ता है? शिक्षा का अधिकार, बराबरी का अधिकार, जीवन साथी चुनने, नौकरी करने या न करने, संतान पैदा करने या न करने, विवाह करने या अविवाहित रहने का अधिकार, यहां तक कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, क्या ये सब अधिकार महिलाओं के व्यक्तित्व का हिस्सा बन पाए हैं। अगर नहीं, तो फिर कैसा सबलीकरण?

महिलाओं को निर्बल बनाकर रखा जा रहा है। उन्हें परंपरा के नाम पर बहुत से अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

हमारे समाज में पुरुष-सत्ता के मूल्यों के आधार पर महिलाओं का समाजीकरण कुछ इस तरह से किया जाता रहा है कि महिला के अस्तित्व को पुरुष से अलग करके देखा ही नहीं जाता। महिलाओं के जीवन से जुड़ा हर निर्णय पुरुष-सत्ता ही तय करती आई है। यह भी एक तथ्य है कि लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन लैंगिक भेदभाव का ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के यौन संबंधी कार्य भी पुरुषों की मर्जी से निर्धारित होते रहे हैं। कुछ नारीवादी विचारक मानते हैं कि स्वतंत्र प्रजनन और यौन कर्म के लिए शोषण को खत्म करना जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब पूंजीवादी व्यवस्था और पितृसत्ता का अंत हो।

स्त्री को नियंत्रित करने के लिए पुरुष हमेशा से 'भय के मनोविज्ञान' का प्रयोग करता रहा है, जैसे कभी परिवार की मर्यादा के नाम पर, कभी उसे शारीरिक और बौद्धिक कमजोरी का यकीन दिला कर, मासिक धर्म के समय उसकी पवित्रता को संदेहास्पद मान कर, पति की सेवा को उसका धर्म और जन्म-मरण से मुक्ति का मार्ग बता कर या फिर संतान उत्पन्न न होने पर उसे मोक्ष न मिलने का तर्क देकर स्त्री को सदा अधीन बनाए रखता है। समाज में इसी तरह की अनेक किवदंतियां और पूर्वाग्रह लंबे समय से चले आ रहे हैं।

विडंबना है कि शिक्षित और आधुनिक समाज भी आज तक इन रूढ़ियों पर अंकुश नहीं लगा पाया या कहें कि लगाना ही नहीं चाहता। ऐसा देखते आए हैं कि विवाह के समय लड़की की उम्र लड़के से कम होनी चहिए, क्यों? शायद कम उम्र की लड़की में परिपक्वता कम होने के कारण उसको नियंत्रित-निर्देशित करना तुलनात्मक रूप से सरल होता है और उसका समाजीकरण मनमाने तरीके से किया जा सकता है। ऐसे में महिला समाजीकरण और उसका सबलीकरण विरोधाभासी नजर आते हैं। '

अगर महिलाओं का समाजीकरण पुरुष-सत्ता के अंतर्गत हुआ है, तो उसके सबलीकरण की बात ही बेमानी हो जाती है। अन्यथा महिला आरक्षण को अब तक लोकसभा में स्वीकृति मिल गई होती। क्या महिलाओं का सबलीकरण पुरुष समाज के समक्ष अनेक चुनौतियों को उत्पन्न करता है, जिसके भय से महिलाओं के आरक्षण विधेयक को पास नहीं होने दिया गया। यह एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है, जिस पर विमर्श करने से भी शायद लोग कतराते हैं। महिलाओं के संदर्भ में ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जिन पर विमर्श या सार्वजानिक चर्चा करने की जरूर सदियों से अनुभव की जाती रही है, पर समाज, राज्य, अकादमिक जगत और बुद्धिजीवी सभी खामोश हैं।

कुछ समय पहले महिला सुरक्षा को लेकर सत्ता के गलियारों में कुछ चर्चा सुनाई दी, पर परिणाम हम सबके सामने है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो महिला सुरक्षा को लेकर लोगों का गुस्सा कुछ देर के लिए दिखने लगता है, पर कुछ समय बाद वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। लड़कियों को देर रात या सांझ के बाद घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए, उन्हें छोटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, उन्हें लड़कों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए जोर-जोर से नहीं हंसना चाहिए, सड़क चलते लड़कों की फब्ती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, आदि।

आखिर ऐसा क्यों? क्यों किया जाता है महिलाओं का ऐसा समाजीकरण? पशु और स्त्री में क्या कोई फर्क नहीं है? या यह मान लिया गया है कि स्त्री के पास केवल शरीर होता है, मस्तिष्क नहीं? वह केवल भावनात्मक प्राणी है, इसलिए बौद्धिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से उसे वंचित रखने का प्रयास जारी है? क्या महिला आरक्षण विधेयक का पास न हो पाना वास्तव में महिलाओं के विशिष्ट समाजीकरण और उसकी पुरुष द्वारा की गई व्याख्या में निहित हैं?

देखा जाए तो महिलाओं के सबलीकरण के यथार्थ को उनके समाजीकरण की विसंगतियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। इस समाजीकरण में महिलाओं के शरीर, पवित्रता-अपवित्रता के

संदर्भ, महिलाओं द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे प्रतीक (विवाह पूर्व, विवाहित, विधवा के रूप में), बच्चों के जन्म तथा पालन-पोषण, रसोई में उनकी भूमिका, ससुराल और पति के बारे में दृष्टिकोण, भाषा के प्रयोग, विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं, यौन संबंधों के सवाल, पोशाक, भोजन संबंधी आदतों आदि के बारे में बताते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चाहे वे घरेलू महिलाएं हों या पेशे से जुड़ी, सभी महिलाओं का समाजीकरण ऐसे ही किया जाता है और इन्हें सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या का भाग बनाया जाता है, क्योंकि इन्हें सहेजने की जिम्मेदारी महिला को सौंपी गई है। अगर ये सभी व्याख्याएं और निर्धारण पुरुष करे तो सबलीकरण कैसा?

कुछ समय पहले महिला सुरक्षा को लेकर सत्ता के गलियारों में कुछ चर्चा सुनाई दी, पर परिणाम हम सबके सामने है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो महिला सुरक्षा को लेकर लोगों का गुस्सा कुछ देर के लिए दिखने लगता है, पर कुछ समय बाद वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। लड़कियों को देर रात या सांझ के बाद घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए, उन्हें छोटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, उन्हें लड़कों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए जोर-जोर से नहीं हंसना चाहिए, सड़क चलते लड़कों की फब्ती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, आदि। आखिर ऐसा क्यों? क्यों किया जाता है महिलाओं का ऐसा समाजीकरण? पशु और स्त्री में क्या कोई फर्क नहीं है? या यह मान लिया गया है कि स्त्री के पास केवल शरीर होता है, मस्तिष्क नहीं? वह केवल भावनात्मक प्राणी है, इसलिए बौद्धिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से उसे वंचित रखने का प्रयास जारी है? क्या महिला आरक्षण विधेयक का पास न हो पाना वास्तव में महिलाओं के विशिष्ट समाजीकरण और उसकी पुरुष द्वारा की गई व्याख्या में निहित हैं?

अभी कुछ समय पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक पति द्वारा दायर तलाक याचिका के मामले में कहा कि अगर विवाहिता हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार मंगलसूत्र, चूड़ियां और सिंदूर लगाने से इनकार करती है, तो यह माना जाएगा कि विवाहिता को शादी अस्वीकार है। यह किस तरह का तर्क है?

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इस तरह का कोई तर्क नहीं दिया गया है कि पत्नी द्वारा इन प्रतीकों का प्रयोग न करने पर विवाह को अवैध माना जाएगा। तो फिर इस निर्णय का आधार क्या है? दूसरा उदाहरण, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था। वर्ष 2005 में संशोधन के बाद उन्हें यह अधिकार मिला, पर इस शर्त के साथ कि यह अधिकार केवल 2005 के बाद जन्मी पुत्रियों को होगा।

वर्ष 2015 में पुन- इस निर्णय को संशोधित किया गया और सभी पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया

गया, जिसे अनेक चुनौतियों के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी है। स्त्री को अपने किसी भी अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष क्यों करना पड़ता है? शिक्षा का अधिकार, बराबरी का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, नौकरी करने या न करने का अधिकार, संतान पैदा करने या न करने का अधिकार, विवाह करने या अविवाहित रहने का अधिकार, यहां तक कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, अपना भविष्य तय करने का अधिकार, क्या ये सब अधिकार महिलाओं के व्यक्तित्व का हिस्सा बन पाए हैं। अगर नहीं तो फिर कैसा सबलीकरण? इन सभी सवालों पर 'महिलाओं की आलोचना' या 'महिलाओं का संकोच' उनके अराजनीतिक और असंगठित होने का सबूत कहा जा सकता है।

महिलाओं की स्वतंत्रता, उदारता, समानता और खुलेपन को परिवार और समाज-विरोधी मान लिया जाता है। इसलिए सिमेन द बोउआ तर्क देती हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र परिवेश से पृथक रखा जाता है और 'निर्भरता से जीवन में संतुष्टि मिलती है', का विचार महिला की चेतना का हिस्सा बना दिया जाता है। परिवार, पति, बच्चे, कपड़े, रसोई पर तो उसे चर्चा करने का हक है, पर इस दायरे के बाहर का विश्व उसके चिंतन का विषय क्षेत्र नहीं हो सकता। पुरुष समाज ने हमेशा महिला को अधीनस्थ बनाया है, जिसे समाप्त किए बिना महिला सबलीकरण का रास्ता तलाशना कठिन है।

वर्तमान दौर में 'ज्ञान शक्ति है' का तर्क यह संकेत देता है कि महिला को भी ज्ञान के क्षेत्र में इतना गहरे उतरना होगा कि वह न केवल हर तरह के भय का सामना कर सके, बल्कि इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में एक शिष्ट जीवन भी जी सके। ज्ञान की इस शक्ति द्वारा ही महिला न केवल अपने शोषण से मुक्ति पा सकती है, बल्कि शक्ति संबंधों में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सकती है और तभी बराबरी का समाज उभार ले सकता है।

रोजगार का संकट

रोजगार का सीधा संबंध मांग से है। मांग होगी ,तो खपत होगी और इस बढ़ी हुई खपत को पूरा करने के लिए उत्पादन करना होगा। उत्पादन के लिए निवेश करना होगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था के चक्र को चलाने के लिए ऐसे उपायों की जरूरत है, जिससे बाजार में मांग बढ़े।

भारत कोरोना महामारी की गिरफ्त में तो है ही, अब इसे बेरोजगारी की महाआपदा का भी सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए बचाव के सबसे पहले उपाय के तौर देश भर में करीब ढाई महीने की पूर्णबंदी की गई थी। इस दौरान सारे दफ्तर, उद्योग, कारखाने बंद रहे और आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि करोड़ों लोगों का काम-धंधा चौपट हो गया और नौकरियां चली गईं। इस वक्त अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ सबसे बड़ा संकट यह है कि लोगों के पास काम नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो पहले से बाजार में नौकरी की तलाश में थे। बेरोजगारी का यह संकट कोई नया नहीं है। पूर्णबंदी से पहले भी बेरोजगारी दर पिछले चार दशक के उच्चतम पर पहुंच चुकी थी। विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े दिखाते हैं कि देश में बेरोजगारी भयावाह स्तर पर पहुंच चुकी है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआइई) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि बेरोजगारी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है। मार्च से जुलाई के बीच देश में 1.9 करोड़ वेतन भोगियों की नौकरी चली गई। यह संख्या उन लोगों की है, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र की हालत का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। बेरोजगारी दर छब्बीस फीसद के स्तर पर पहुंच चुकी है। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है। हां, इतना जरूर हुआ है कि असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार, जिनमें बड़ी तादाद दिहाड़ी मजदूरों की है, उन्हें अब फिर से रोजगार मिलना शुरू हुआ है। सीएमआइई ने पिछली रिपोर्टों में बताया था कि सिर्फ अप्रैल महीने में देश में बारह करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग बेरोजगार हो गए थे। जुलाई में यह संख्या घट कर एक करोड़ के आसपास रह गई, यानी ग्यारह करोड़ लोग वापस काम पर लग चुके हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी काम पाना उतना कठिन नहीं होता, जितना संगठित क्षेत्र में नौकरी पाना। बुरा हाल तो उन बेरोजगार युवाओं का है, जो कहीं न कहीं नौकरी कर रहे थे और हर महीने वेतन पा रहे थे। लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां गईं, तो लोगों को वेतन मिलना बंद हो गया। कोरोना संकट के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में रोजगार की स्थिति को लेकर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की हालिया रिपोर्ट (टैक्लिंग द कोविड-19 यूथ एंप्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक) के अनुसार इस साल के अंत तक भारत के इकतालीस लाख नौजवान नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। पूर्णबंदी के दौरान खड़े हुए बेरोजगारी के इस संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल 'असीम' (आत्मनिर्भर स्किल्ड एंप्लॉई-एंप्लॉयर मैपिंग) की भी व्यवस्था की है। इस पोर्टल पर पिछले चालीस दिनों में उनहत्तर लाख बेरोजगारों ने नौकरी की तलाश में अपने को पंजीकृत किया। कुल पंजीकृत लोगों में सिर्फ सात हजार सात सौ को काम मिला। मतलब यह कि 0.1 फीसद लोगों, यानी एक हजार व्यक्तियों में से सिर्फ एक आदमी को काम मिला। इसी पोर्टल पर 14 से 21 अगस्त के बीच, महज एक सप्ताह में सात लाख लोगों ने पंजीकरण कराया, जिसमें मात्र छह सौ इक्यानबे लोगों को ही काम मिला। काम मिलने का अनुपात ज्यों का त्यों बना रहा, जो 0.1 फीसद से भी कम है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में जिस तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके अनुपात में रोजगार मिलने की संभावनाएं अतिन्यून हैं, बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि नहीं के बराबर हैं। दिलचस्प तो यह है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर पिछले कई वर्षों से रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। जाहिर है, सरकार उपभोग, रोजगार और अन्य आर्थिक आंकड़ों को दबाए रखना चाहती है, ताकि विस्फोटक होती स्थिति सामने न आने पाए। अब तो राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श कार्यालय (एनएसएसओ) को भी खत्म कर दिया गया है। इसका विलय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) में करके नया संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) बना दिया गया है। एनएसओ संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संस्थान एक सरकारी अंग होगा और इसकी जावाबदेही सरकार के प्रति होगी। रोजगार पर पहली चोट नोटबंदी से लगी थी। इसके बाद कोरोना महामारी ने बची-खुची कसर पूरी कर दी। बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े सरकारी नीतियों की सफलता पर प्रश्नचिह्न लगाने वाले हैं। ऐसे आंकड़ों को जारी न करना और बिना आंकड़ों के ही नीति बनाना आंकड़ागत रूढ़िवाद है। प्रख्यात पत्रकार क्रिस एंडर्सन ने आंकड़ागत रूढ़िवाद के संदर्भ में कहा भी था- 'पर्याप्त आंकड़े होने पर संख्याएं स्वयं अपनी सच्चाई बयान करती हैं।' सरकार ने इस कथन को अक्षरशः लिया है। रोजगार की वास्तविक स्थिति को अगर छिपाना है, तो पर्याप्त आंकड़ों का खुलासा ही न करना बेहतर है।

लेकिन पर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता समस्या निवारण का बुनियादी कदम है। मसलन, अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसका सफल इलाज तभी हो सकेगा, जब यह पता चले कि कैंसर शरीर के किस हिस्से और कितनी घातक स्थिति में है। इसके लिए कैंसर संबंधी जांचें जरूरी हैं, न कि दूसरे अनावश्यक आंकड़े। यही हाल मौजूदा अर्थव्यवस्था का भी है। रुग्णता से जूझ रही अर्थव्यवस्था का इलाज कैसे हो, इसके लिए सही आंकड़ों की अत्यंत आवश्यकता है। असीम जॉब पोर्टल असल में एक ऐसा ऑनलाइन ठिकाना है जहां से नियोक्ता को वांछित योग्यता वाले कर्मचारी मिल सकें और नौकरी तलाश करने वालों को नियोक्ता। जाहिर है, यह तभी कारगर होगा जब श्रम-बाजार में श्रमिकों की मांग होगी।

फंसे कर्ज का मर्ज

कोरोना महामारी के कारण बैंकों के परिचालन लाभ में सत्ताईस फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। अब आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ने का अंदेशा है। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हालात के चलते आगामी महीनों में एनपीए की स्थिति और बिगड़ने का खतरा सामने है। रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल मार्च तक सकल एनपीए का स्तर बढ़ कर 14.7 फीसद हो सकता है।

तकनीकी तौर पर एनपीए में तब्दील होने से पहले किसी खाते को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

भारत की अर्थव्यवस्था संकट भरे दौर से गुजर रही है। खासकर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की हालत ठीक नहीं है। अधिकांश कंपनियां, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, कर्ज की किस्तों और ब्याज का भुगतान महीने के आखिरी सप्ताह या महीने के आखिरी दिन कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों के कर्ज खाते इसलिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में तब्दील नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वे अंतिम समय में किस्त चुका दे रहे हैं। हालांकि उनकी वित्तीय स्थिति भी खस्ताहाल है। इसलिए ऐसे उद्योगों एवं अन्य ग्राहकों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कंपनियों, एमएसएमई क्षेत्र की कंपनियों और खुदरा व व्यक्तिगत कर्ज खातों के पुनर्गठन की अनुमति दे दी है। कर्ज पुनर्गठन की सुविधा उन्हीं कर्जदारों को मिलेगी, जिन्होंने एक मार्च,2020 तक कर्ज भुगतान में तीस दिन से अधिक देरी नहीं की थी। ऐसे कर्ज खातों का पुनर्गठन 31 दिसंबर तक किया जा सकता है।

तकनीकी तौर पर एनपीए में तब्दील होने से पहले किसी खाते को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ऐसे खाते स्पेशल मेंशन अकाउंट्स (एसएमए) के नाम से जाने जाते हैं। एसएमए-0, वे खाते होते हैं, जिनमें भुगतान में तीस दिनों तक की देरी हुई है। एसएमए-1 वे कर्ज खाते होते हैं जिनमें इकतीस से साठ दिन तक भुगतान बकाया रहता है। और फिर इकसठ से नब्बे दिनों तक भुगतान बकाया रहने पर खाते एसएमए-2 में रखे जाते हैं। अगर भुगतान नब्बे दिनों से अधिक बकाया रहता है तो खाते एनपीए में तब्दील हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के कर्ज खातों के एसएमए के किसी भी श्रेणी में रहने पर पुनर्गठन की अनुमति दे दी है, लेकिन शर्त यह है कि कर्जदार को कुल पच्चीस करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं दिया गया हो। पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक कर्ज लेने वाले उद्योग जो एसएमए-1 और एसएमए-2 श्रेणियों में आते हैं, उनके कर्ज का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, अर्थात एमएसएमई सहित जिन उद्योगों ने पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है और चुकाने में तीस दिनों से ज्यादा की चूक की है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कुछ बैंकों को छोड़ कर अधिकांश बैंकों का एनपीए जून तिमाही में कम हुआ है। लेकिन सितंबर और दिसंबर तिमाही में एनपीए में बढ़ोतरी की आशंका है। हालांकि जून तिमाही में भी कुछ बैंकों ने परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट आने का अनुमान लगा कर एनपीए के लिए प्रावधान किए हैं। बैंकों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने में अभी भी समय लगेगा, जिससे कर्ज अदायगी स्थगन का लाभ लेने वाले कर्जदारों को कर्ज की किस्त एवं ब्याज चुकाने में और भी समय लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज पर पहले मार्च से जून और फिर अगस्त तक छह महीनों के स्थगन की घोषणा की है। दबकि बैंकों का कहना है कि कर्ज की किस्त और ब्याज का स्थगन समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि विमानन, पर्यटन, यात्रा और निर्माण जैसे प्रभावित उद्योगों को कर्ज स्थगन सुविधा का लाभ देने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति में तुरत-फुरत में सुधार आना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि कर्ज की किस्तों और ब्याज स्थगन की योजना कर्जदारों के बीच लोकप्रिय नहीं है। एक अनुमान के अनुसार केवल पंद्रह फीसद कारपोरेट कंपनियों ने ही इस विकल्प को चुना है, जबकि खुदरा क्षेत्र में सिर्फ बीस से तीस फीसद लोगों ने यह विकल्प चुनना उचित समझा। अगर सभी क्षेत्रों को मिला दिया जाए, तो कुल तीस फीसद कर्जदारों ने कर्ज पुनर्गठन के विकल्प को चुना। दरअसल किस्त एवं ब्याज को टालना अस्थायी प्रक्रिया है और इसकी एक सीमा है। लंबे समय तक इस प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता है। ऐसा करने से कर्ज की राशि, टाली गई राशि को मिला कर इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसकी वसूली बैंकों के लिए असंभव हो जाएगी। कर्ज अदायगी स्थगन की सुविधा की जगह कर्ज खातों का पुनर्गठन ज्यादा व्यवहारिक है, लेकिन यह भी सभी के लिए नहीं होना चाहिए। यह सुविधा सिर्फ प्रभावित उद्योगों और व्यक्तियों को ही दी जानी चाहिए। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना महामारी बैंकों पर कितना असर डालेगी। यदि अगस्त महीने में कर्ज अदायगी का स्थगन समाप्त हुआ, तो एनपीए की वास्तविक तस्वीर चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में दिख सकती है। जून, 2020 की तिमाही में कर्जों के भुगतान पर रोक से परिसंपत्ति गुणवत्ता पर काफी दबाव रहा। इस तिमाही में बैंकों को एनपीए के मद में बड़ी राशि का प्रावधान करना पड़ा। प्रमुख निजी बैंकों की पहली तिमाही के आय विश्लेषणों से पता चलता है कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में कमी की वजह से समग्र आधार पर आकस्मिक प्रावधान किए गए। कोरोना महामारी के कारण बैंकों के परिचालन लाभ में सत्ताईस फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। अब आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ने का अंदेशा है। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हालात के चलते आगामी महीनों में एनपीए की स्थिति और बिगड़ने का खतरा सामने है। रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल मार्च तक सकल एनपीए का स्तर बढ़ कर 14.7 फीसद हो सकता है। यदि मार्च 2021 तक सकल एनपीए 14.7 फीसद हुआ तो यह पिछले बाईस वर्षों का उच्चतम स्तर होगा। इससे पहले वर्ष 1999 में सकल एनपीए 15.9 फीसद के स्तर पर पहुंच गया था, जो वर्ष 2000 में घट कर 14 फीसद और वर्ष 2003 में 9.3 फीसद रह गया था।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों की स्थिति निजी बैंकों से ज्यादा खराब हो सकती है। भारी-भरकम एनपीए का असर बैंकों की पूंजी और कर्ज देने की क्षमता पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की वजह से कम से कम पांच बैंक अगले मार्च तक न्यूनतम पूंजी स्तर का पालन करने में चूक कर सकते हैं। इस साल सितंबर तक तिरपन देशी-विदेशी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात कम होकर 14.1 फीसद होने का अनुमान है, जो सितंबर 2019 में 14.9 फीसद थी। निजी बैंक पूंजी बढ़ा चुके हैं या इस प्रक्रिया में हैं। सरकार को अभी सरकारी बैंकों में पूंजी डालने की योजना की घोषणा करनी है। बजट में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जिन बैंकों को पूंजी नहीं मिलेगी, उनकी वित्तीय स्थिति का खराब होना लगभग तय है। इस रिपोर्ट में निजी बैंकों का एनपीए अनुपात 3.1 फीसद से 4.5 फीसद के बीच बढ़ने का अनुमान है। भारत में कोरोना की दस्तक से पहले तक बैंकों के एनपीए का स्तर घट रहा था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी मजबूत था। इसलिए माना जा रहा है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न संकटों से निपटने में भी भारतीय बैंक कामयाब रहेंगे। वित्त वर्ष 2012-13 में बैंकों ने बड़े पैमाने पर कर्ज खातों का पुनर्गठन किया था। फिर भी, वे संकट से उबर गए थे। कोरोना संकट के चलते कर्ज की लागत बढ़ गई है। आगामी महीनों में एनपीए बढ़ने की संभावना भी प्रबल है।

भारत की इन जगहों पर ले सकते हैं हॉट एयर बैलून का मजा

विदेश यात्रा

में आपको कई जगहों पर हॉट एयर बैलून में घूमने का मौका मिलेगा

कर्नाटक के वेस्ट कोट में भी हॉट एयर बैलून का मजा लिया जा सकता है। यहां पर आप हॉट एयर बैलून की सवारी के साथ-साथ भारत के ऐतिहासिक शहर हम्पी की विभिन्न गुफाओं, मंदिरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए कुछ समय व्यतीत करें।

जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी और काम के अत्यधिक बोझ से निजात पाना चाहते हैं तो वह एक ऐसी छुट्टी पर जाने की इच्छा रखते हैं, जहां उन्हें कई नए एक्सपीरिएंस लेने का मौका मिले। नई जगहों को एक्सप्लोर करते हुए ढेर सारी मस्ती और कुछ एडवेंचर्स करने की चाह हर घुमक्कड़ के मन में होती है। ऐसे में हॉट एयर बैलून का मजा लिया जा सकता है। इसका अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस हैं। वैसे तो विदेश यात्रा में आपको कई जगहों पर हॉट एयर बैलून में घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप भारत में होते हुए हॉट एयर बैलून का मजा लेना चाहते हैं तो इन जगहों पर जा सकते हैं-

महाराष्ट्र-अगर आपको हॉट एयर बैलून का मजा लेना है तो महाराष्ट्र के लोनावला में जाया जा सकता है। जहां आपको इसकी सवारी के दौरान इस क्षेत्र की हरी-भरी हरियाली पहाड़ियों का नजारा देखने को मिलेगा। अगर आप मुंबई में हैं तो महज डेढ़ घंटे का रास्ता तय करके आप इस खूबसूरत जगह पर पहुंच सकते हैं। यहां पर हॉट एयर बैलून का मजा लेने के लिए आपको प्रति व्यक्ति करीबन 6000 से 12000 रूपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं एक राइड के दौरान आपको करीबन 60 मिनट तक बैलून में घूमने का मौका मिलेगा।

कर्नाटक-कर्नाटक के वेस्ट कोट में भी हॉट एयर बैलून का मजा लिया जा सकता है। यहां पर आप

हॉट एयर बैलून की सवारी के साथ-साथ भारत के ऐतिहासिक शहर हम्पी की विभिन्न गुफाओं, मंदिरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए कुछ समय व्यतीत करें।

दिल्ली एनसीआर और हरियाणा-सुनने में आपको शायद अजीब लगे लेकिन दिल्ली, एनसीआर में रहकर भी आप हॉट एयर बैलून का मजा ले सकते हैं। स्काई वॉल्ट्ज सरकार द्वारा अप्रूव्ड हॉट एयर बैलून सफारी कंपनी है जो पूरे भारत में चालू है। दिल्ली में रहते हुए भी आपको हॉट एयर बैलून की सवारी करने का मौका मिल सकता है। स्काई वॉल्ट्ज कंपनी की मदद से आप दिल्ली के अलावा, नीमराणा, पुष्कर, जयपुर और लोनावाला के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं।

अगर घूमने के हैं शौकीन तो चुनें सस्ता और खूबसूरत देश मिस्र

जैसा कि आप सबको पता है कि पर्यटन की स्थिति संपूर्ण विश्व में कोविद-19 के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी हाल में ही ये घोषणा की है कि वे आने वाले दिनों में- संभवतः जून महीने के अंत या फिर जुलाई की शुरुआत में अपने अंतर्राष्ट्रीय बार्डर खोल सकते हैं और कुछ सीमित देशों के पर्यटक को अपने देश में घूमने की इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने फिलहाल अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 जून तक रद्द की हैं। हालांकि घरेलू उड़ानें जो कि 22 मार्च से प्रतिबंधित थीं, पुनः 25 मई से शुरू की जा चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने अभी हाल में ये बयान दिया है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को अगस्त से पहले पुनः आरम्भ करने के बारे में सोच रही है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को या तो खोल चुके हैं या बहुत जल्द खोलने की आधिकारिक घोषणा कर चुके हैं। मगर कुछ नयी गाइडलाइन्स के तहत। आइए, हम इन देशों में शुमार एक ऐसे देश का ज़िक्र करते हैं जिसने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की है कि वो अपनी सीमाएं पर्यटकों के लिए जुलाई 1 से पुनः खोल देंगे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को देश में लैंड करने की इजाज़त दे देंगे। और वो देश है मिस्र यानी Egypt। वहां की कैबिनेट ने कहा है कि कोविद-19 की वजह से जो प्रतिबन्ध लगाए गए थे, उनमें कुछ ढील दी जाएगी- मसलन रात्रि कर्फ़्यू में कुछ छूट, दुकानों के खुलने के समय में कुछ इज़ाफा इत्यादि। मिस्र के सूचना राज्य मंत्री ओसामा हैकल ने एक टेलीविज़न ब्रीफिंग में बताया कि रिसोर्ट बीचेस को भी खोल दिया जायेगा किंतु पब्लिक बीचेज़ अभी विचाराधीन हैं।

भौगोलिक स्थिति-मिस्र उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक ऐसा देश हैं जो मुख्यतः दो हिस्सों में विभाजित है- उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण-पश्चिम एशिया। इसके पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाज़ा पट्टी और इस्राइल तथा दक्षिण में सूडान स्थित है। मिस्र की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा नील नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में रहता है। मिस्र को इसके प्राचीन इतिहास, सभ्यता, रेगिस्तानी परिदृश्य और विशाल पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसका आधिकारिक नाम मिस्र अरब गणराज्य है। राजधानी कैरो और भाषा अरबी है। यहां की करेंसी Egyptian Pound है। यहां की जलवायु गर्म रेगिस्तान, शुष्क गर्मी और मध्यम ठंड है। मिस्र का मूल धर्म इस्लाम है जो समाज के हर पहलू को नियंत्रित करता है और कानून से समर्थित है। वैसे तो मिस्र में जाने का सही समय अक्टूबर से अप्रैल है जब तापमान अधिक नहीं होता, किन्तु पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयुक्त समय दिसंबर और जनवरी होता है।

मिस्र के पिरामिड

सम्पूर्ण इतिहास जगत में मिस्र का अत्यधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय प्रतीक निःसंदेह वहां का पिरामिड है। जैसे ही मिस्र देश का नाम जुबान पर आता है, मानसपटल पर वहां के पिरामिड अनायास ही परिलक्षित हो जाते हैं। वास्तव में मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन फैरों यानी सम्राटों के स्मारक स्थल हैं जिसके अंदर वहां के राजाओं और रानियों और बहुत से बहुचर्चित हस्तियों के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। पिरामिड का आकर त्रिभुजाकार होता है और यदि इसके किनारों की लम्बाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाय तो बहुत सारी चीज़ों की गणना की जा सकती है खासकर जो पृथ्वी से संबंधित हो। इसीलिए पिरामिड को गणित की कुंडली भी कहा जाता है। पिरामिड के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाये गए हैं ताकि उसका औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना रहे और भूकंप से भी सुरक्षित रहे। वैसे तो मिस्र में कुल 138 पिरामिड हैं मगर इन सब में 'गीज़ा का ग्रेट पिरामिड' ही सबसे प्रख्यात है और दुनिया के सात प्राचीनतम आश्चर्य में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 450 फ़ीट है। बड़े बड़े चूना पत्थरों के ब्लॉक से इसे निर्मित किया गया है। इसके अलावा कुछ प्रमुख पिरामिड के नाम हैं-

- खूफ़ू का पिरामिड
- खाफरे का पिरामिड
- बेंट पिरामिड
- रेड पिरामिड
- डेजोसेर का स्टेप पिरामिड
- मेंकौरे का पिरामिड
- मेडुम का पिरामिड
- उनस का पिरामिड
- तेती का पिरामिड
- हवारा का पिरामिड
- उसेरकाफ का पिरामिड
- लहुं का पिरामिड

मिस्र एक ऐसा गंतव्य है जो न कि सिर्फ पिरामिड के लिए मशहूर है बल्कि वहां पर बहुत सारे मक़बरे, मंदिर और प्राचीन फैरों के घर हैं।

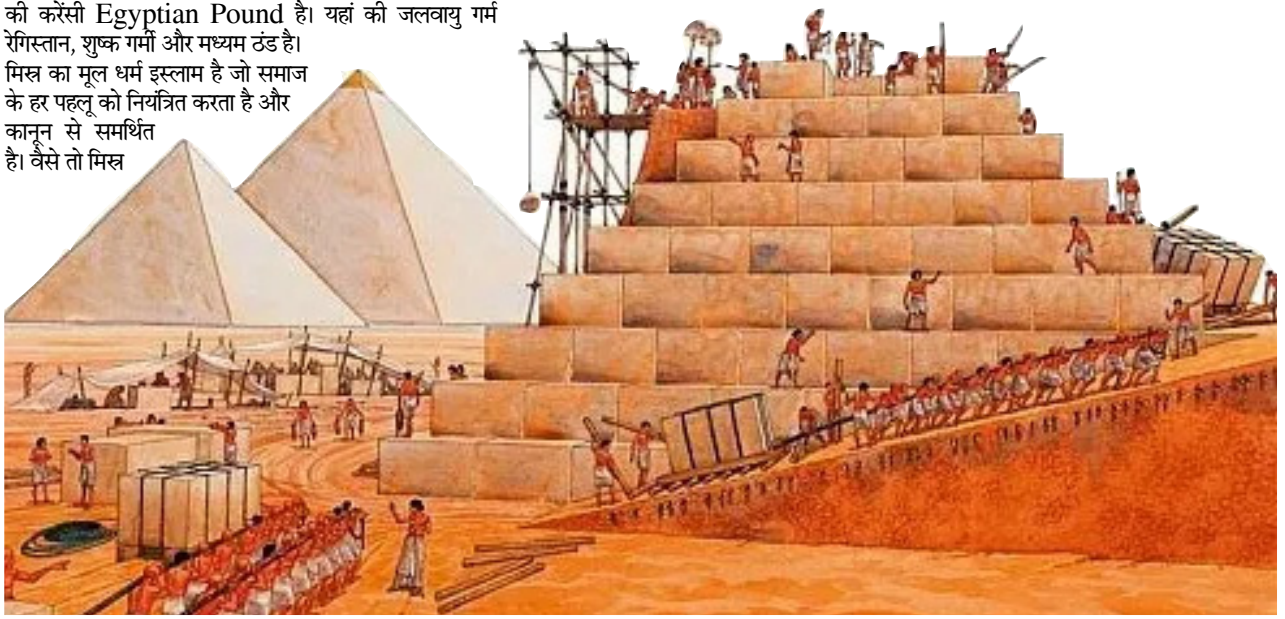

डिजिटल कक्षाओं का ऑनलाइन देखा हाल, बाढ़ और बारिश से गाँव-शहर बेहाल...

क्या यही न्यू इंडिया है?

इस सप्ताह के कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे रहे। टीवी चैनलों पर चौबीसों घंटे दिखाये जाने वाले कई मुद्दे देश के वास्तविक मुद्दों से बड़े हो गये हैं। ऐसे में हम आपके समक्ष आज उन मुद्दों को लेकर आये हैं जो देखने-सुनने में सामान्य या छोटे भले लगें लेकिन यही वास्तविक मुद्दे हैं। भारत में कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है ताकि बच्चों का कोर्स पूरा कराया जा सके लेकिन शहरों और गाँवों के बीच खाई इतनी ज्यादा है कि गांव तो छोड़ दीजिये शहरों में भी अधिकांश बच्चों के पास स्मार्ट फोन या लैपटॉप नहीं है। गाँवों में इंटरनेट की समस्या है तो डेटा पैक रिचार्ज कराने का एक नया खर्च बढ़ जाने से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं कई जगह से तो ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि चूँकि अभिभावक बच्चों की स्कूल की फीस देने में असमर्थ दिखे तो उनके बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। हालाँकि जब-जब ऐसे मामले प्रशासन के संज्ञान में लाये जाते हैं तो कार्रवाई होती है। इसके अलावा सरकार ने कम्युनिटी लर्निंग की व्यवस्था की है और शिक्षा के लिए कुछ टीवी चैनल भी शुरू किये गये हैं जोकि विभिन्न भाषाओं में पढ़ाई करा रहे हैं साथ ही रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई जा रही है लेकिन यह भी दिक्कत है कि पिछड़े इलाकों में कई घरों में अब भी टीवी नहीं होते तो ऐसे में उनके बच्चों की शिक्षा का क्या होगा?

इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और वर्षाजनित हादसों में लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। इस साल मानसून को देखें तो पिछले वर्ष से ज्यादा कहर बरपाया है। वर्षाजनित हादसे हर साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा बड़ी आपदा लेकर आते हैं और हम सिर्फ उसे देखते रहते हैं और जब आपदा सामने आ खड़ी होती है तो बचाव और राहत कार्य शुरू करते हैं। आजादी के 7 दशक से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी यदि हम बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यह न्यू इंडिया है या फिर हम विकासशील से विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इस साल बाढ़ और वर्षाजनित हादसों में लगभग 1000 लोग मारे गये हैं यही नहीं लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। सवाल है कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार?

दूसरी ओर भारतीय रेलवे की ओर से नये कीर्तिमान रचे जाने का दौर जारी है। रेलवे अपनी पुख्ता तैयारियों की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देना जारी रखे हुए है। रेलवे की फ्रेट कॉरिडोर योजना और घर से घर तक सामान पहुँचाने की योजना आने वाले दिनों में रेलवे की तसवीर बदल कर रख देगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी काम जारी है। रेलवे ने जिस तरह कोरोना काल में लोगों की सेवा का कार्य जारी रखा हुआ है वह सराहनीय है।

● भारत में कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है ताकि बच्चों का कोर्स पूरा कराया जा सके लेकिन शहरों और गाँवों के बीच खाई इतनी ज्यादा है कि गांव तो छोड़ दीजिये शहरों में भी अधिकांश बच्चों के पास स्मार्ट फोन या लैपटॉप नहीं है। गाँवों में इंटरनेट की समस्या है तो डेटा पैक रिचार्ज कराने का एक नया खर्च बढ़ जाने से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं कई जगह से तो ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि चूँकि अभिभावक बच्चों की स्कूल की फीस देने में असमर्थ दिखे तो उनके बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में बैठने ही नहीं दिया जा रहा है।

पहली बार पांच को मिले 'खेल रत्न' पुरस्कार

खिलाड़ियों को सरकार दे रही विशेष प्रोत्साहन

टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में 30 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें क्रिकेट की कोचिंग दिलाई जा सके। एक जमाना था, जब हम बचपन में सुनते थे, 'खेलोगे कूदोगे, बनोगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब।' लेकिन आज खेलों की दुनिया कैरियर को लेकर भी पूरी तरह बदल चुकी है। खेल अब महज खेल नहीं रह गए हैं बल्कि कैरियर का बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहे हैं। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए अब पैसे और मान-सम्मान की कोई कमी नहीं है। खेल जगत का इतिहास ऐसे अनेक खिलाड़ियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने बेहद गरीबी और संघर्षों के दौर से गुजर कर अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने शानदार खेल प्रदर्शन से पूरे देश का नाम दुनियाभर में रोशन किया। ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों को हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष कुल सात केटेगरी के 74 खिलाड़ियों और कोचों को कोरोना के चलते पहली बार हुए वर्चुअल समारोह में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल सम्मान 'राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' पहली बार कुल पांच खिलाड़ियों- क्रिकेटर रोहित शर्मा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, पहलवान विनेश फोगाट तथा पैरालम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थांगावेलू को प्रदान किया गया। इससे पहले 2016 में एक साथ चार खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला था। तब रियो ओलम्पिक में रजत जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, महिला रेसलिंग में कांस्य जीतने वाली साक्षी मलिक के अलावा जिमनास्ट दीपा कर्माकर तथा शूटर जीतू को यह सम्मान मिला था। जैसा कि इस सम्मान के नाम से ही जाहिर है कि यह पुरस्कार खेल जगत के रत्नों अर्थात् विभिन्न खेलों में असाधारण प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और साढ़े सात लाख रुपये प्रदान किए जाते थे लेकिन पुरस्कार राशि बढ़ाकर इस बार से 25 लाख रुपये कर दी गई है। खेल रत्न पुरस्कार की शुरूआत 1991-92 में की गई थी और तब शतरंज के ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को पहली बार यह सम्मान प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ था। 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा महज 18 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। अभी तक कुल 43 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। 12 सदस्यीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ओलम्पिक, पैरालम्पिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद ही अपनी सिफारिशें खेल एवं युवा मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजती है। इस वर्ष जिन पांच खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कड़ा संघर्ष करने के बाद इस मुकाम को छुआ है। तमिलनाडु के सालेम जिले में एक बहुत गरीब परिवार में जन्मे मरियप्पन के पिता बहुत सालों पहले ही परिवार छोड़कर चले गए थे और मां सरोजा ने सब्जियां बेचकर परिवार का भरण-पोषण किया। जब मरियप्पन पांच साल के थे, तब एक बस उनके पैर के ऊपर से गुजर जाने के कारण उनका पैर कट गया था। उस भयानक सड़क दुर्घटना के बाद 17 साल की लंबी अदालती लड़ाई के पश्चात् उनके परिवार को केवल दो लाख रुपये मुआवजा मिला, जिसमें से एक लाख रुपये वकीलों की फीस में चले गए और एक लाख मरियप्पन के भविष्य के लिए बैंक खाते में जमा कर दिए गए। उनके इलाज के लिए लिया गया तीन लाख रुपये का ऋण भी उनके द्वारा पैरालम्पिक में गोल्ड मैडल जीते जाने तक नहीं चुकाया जा सका था। उन्होंने 2016 के रियो पैरालम्पिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक हासिल कर देश को गौरवान्वित किया। पैरालम्पिक में भारत के लिए पदक जीतने पर केन्द्र सरकार ने उन्हें 75 लाख रुपये और तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने दो करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की थी। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा का जीवन भी

संघर्षों से भरा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में 30 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें क्रिकेट की कोचिंग दिलाई जा सके। उनके चाचा और कुछ मित्रों द्वारा छोटी-छोटी राशि एकत्र करने के बाद उनका दाखिला एक छोटी सी अकादमी में करवाया गया। वहां उन्होंने अपनी प्रतिभा से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और एक क्रिकेट शिविर में कोच दिनेश लाड का ध्यान उन पर गया। उसके बाद उन्होंने अगले चार साल तक रोहित के लिए स्कॉलरशिप का प्रबंध करा दिया और फिर रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी स्पिन गेंदबाजी से क्रिकेट कैरियर की शुरूआत करने के बाद वे कब मध्यम क्रम बल्लेबाजी से टीम इंडिया के एक सफल और भरोसेमंद ओपनर और टेस्ट मैचों के सलामी बल्लेबाज बन गए, पता ही नहीं चला। आज रोहित के नाम रिकॉर्डों का ऐसा अंबार लगा है कि उन्हें रिकॉर्डों का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। महिला हॉकी टीम की कप्तान 25 वर्षीया रानी रामपाल का जीवन भी अभावों के दौर से गुजरा। उनके पिता रामपाल घोड़ा गाड़ी चलाकर और ईंटें बेचकर परिवार का गुजारा किया करते थे। रानी को बचपन से ही हॉकी खेलने का शौक था लेकिन उनके शौक को पूरा करने में गरीबी आड़े आ रही थी। फिर भी रानी की जिद के आगे पिता उन्हें हॉकी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए तैयार हो गए। जैसे-तैसे रानी का दाखिला शाहबाद हॉकी अकादमी में हो गया और गुरू द्रोणाचार्य अवार्डी कोच बलदेव सिंह के सानिध्य में रानी की प्रतिभा ऐसी चमकी कि 15 साल की उम्र में ही वह सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी के रूप में विश्व कप में भाग लेने वाली टूर्नामेंट की शीर्ष फील्ड गोल स्कोरर रही और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुनी गई। उसके बाद रानी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर कई पुराने रिकॉर्ड तोड़े और भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शानदार जीत दिलाई।

बॉलिवुड के टॉप 3 सुपरस्टार्स संग साइन की हुई फिल्में

छीन ली गई थीं मुझसे-नीतू चंद्रा

अभिनेत्री नीतू चंद्रा बताती हैं कि एक समय ऐसा था, जब उन्हें लगातार फिल्मों से बाहर निकाला जा रहा था और वह शर्म से झुकती जा रही थीं, कुछ ही दिनों में वह एक के बाद एक 6 बहुत बड़ी फिल्मों से आउट कर दी गईं... जब काम छीना जा रहा होता है, सोशली आपको लोगों से काट दिया जाता है, तब आपके अंदर मानसिक युद्ध भी चल रहा होता है, यह बहुत ही कठिन समय होता है।

बॉलिवुड की बेहतरीन अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने नवभारतटाइम्स डॉट कॉम के साथ फेसबुक पर हुई लाइव बातचीत में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस ने सभी को तोड़ दिया है। बॉलिवुड में शुरू में तो उनको खूब काम मिला, लेकिन बाद में न जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक के बाद एक लगातार आधी दर्जन साइन की हुई फिल्मों से बाहर कर दिया गया। नीतू बताती हैं कि उन्होंने फिल्में भी साइन की थीं, जिनमें बॉलिवुड के टॉप 3 सुपरस्टार्स थे।

3 साल बाद मुझसे सब कुछ छीन लिया गया-बॉलिवुड ने मुझे सिर्फ 3 साल इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया, उसके बाद सचमुच मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। 2005 में मेरी फिल्म गरम मसाला रिलीज़ हुई और 4 साल बाद ही साल 2009 की जब शुरूआत ही हुई थी कि कैंसर की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया। पिता की मौत से उबर कर जब वापसी की तो मेरी साइन की हुई फिल्में मुझसे छीनी जा रही थीं और कुछ ही दिनों में मेरे हाथ से एक के बाद एक 6 फिल्में निकल गईं।

धड़ाधड़ छीनी गईं मुझसे 6 फिल्में-हर महीने, हर हफ्ते एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवीं और फिर छठवीं फिल्म, धड़ाधड़ मुझसे छीन ली गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि लोग क्यों मुझे अपनी फिल्मों से निकाल रहे थे। कोई न तो फोन उठा रहा था, न कोई जवाब दे रहा था। बाहर से आए ऐक्टर्स ऐसे में हेल्पलेस होते हैं।

बिहार की 12 करोड़ जनता से है मेरी शिकायत-कंगना रनौत और तापसी पन्नू की लड़ाई अलग है। मेरी लड़ाई तब भी अपने लोगों से थी और आज भी अपने लोगों से ही है। बिहार की 12 करोड़ की जनता अगर हमारी फिल्म देखे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नार्थ के लोग अगर हमारी फिल्में देखे और हमको प्यार दे तो हम भी फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। कोई यहां किसी का कर्जा खा कर नहीं बैठा है, हम तो अपने बिहार के लोगों से उम्मीद कर सकते हैं, जब अपने लोग ही हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं। बिहार के मेरे अपने लोग, भले मेरी इस बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन देर-सबेर उनको यह मानना ही होगा।

सुशांत सिंह राजपूत ने भी यही कहा था...

सुशांत सिंह राजपूत ने भी तो यही कहा था कि बिहार के लोगों आप हमारी फिल्में देखिए, वरना बॉलिवुड के लोग फिल्म इंडस्ट्री में हमें टिकने नहीं देंगे। आप एक बार सोचिए जब एक साथ आपको 6-6 फिल्मों से निकाला ज्यादा है तो किस तरह का आघात पहुंचता है आपको।

जो सिर गर्व से उठा था, अब जा रहा था

जो सिर गर्व से उठ रहा था, फिल्में छीने जाने पर वही सिर शर्म से झुकता जा रहा था, क्योंकि उन फिल्मों के वर्कशॉप के लिए मैं कई अन्य फिल्मों को करने से इनकार कर रही थी। रातों-रात आपकी फिल्में छिनती हैं तो आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, बाद में पता चलता है कि आपकी जगह उस फिल्म में किसी और को कास्ट किया गया है।

टॉप 3 सुपरस्टार्स की फिल्मों से साइन करने के बाद निकाला गया मुझे

आपको बता दूं कि मुझे ऐसी फिल्मों से बाहर किया गया, जिनमें मेरे साथ बॉलिवुड के टॉप 3 सुपरस्टार्स काम करने वाले थे। मैंने उस समय तक टॉप के सभी डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया था। मुझे बहुत कम समय में ही 9 नैशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर्स के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मधुर भंडारकर, जगमोहन मुंद्रा, दिबाकर बनर्जी, प्रियदर्शन, अनीस बज्मी, सूर्या, विशाल, माधवन, जे एम रवि, नागार्जुन और राम गोपाल वर्मा सहित कई दिग्गजों संग काम

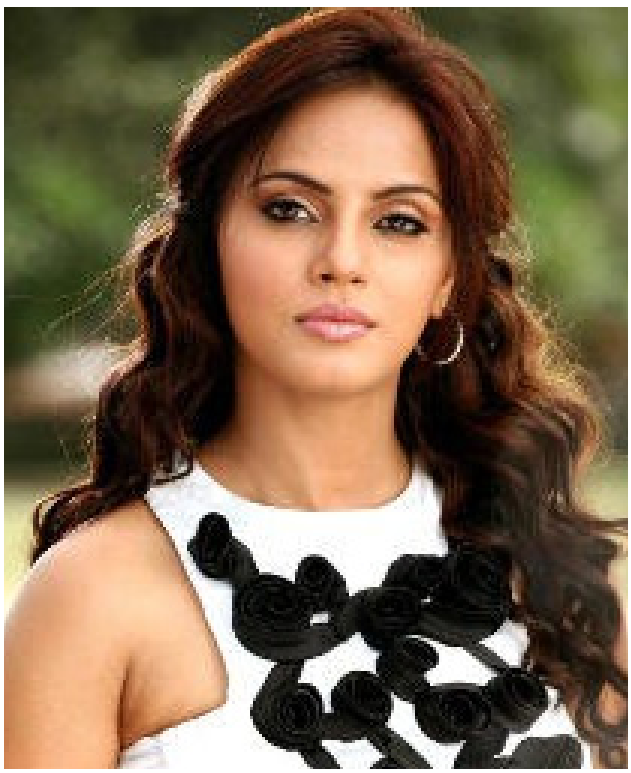

करने का मौका मिल चुका था।

फिल्मों से निकाले जाने के बाद, अपनी इज्जत बचाने में जुट गई थी मैं

फिर क्या वजह थी कि मुझे फिल्मों से निकाला जा रहा था। 6 फिल्मों से निकाली गई तो अपने आप में सिंक हो गई थी मैं, सिंक हुए आदमी को फिर से सामान्य होने में बहुत वक्त लगता है। फिल्म से निकाले जाने के बाद आपको अपनी इज्जत भी बचानी पड़ती है, तब आप खुद को निकालने वालों के सामने मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं सर... उम्मीद करती हूं कि अगली फिल्म हम साथ कर लेंगे। वह जवाब में कहते थे कि हां.. नीतू... प्रड्यूसर आ गया तो प्रेशर में हमें दूसरी हिरोइन को लेना पड़ा, क्योंकि उस हिरोइन का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, जिससे फिल्म को सपॉर्ट मिल जाएगा।

हमें कुपोषण मुक्त भारत के लिए किस तरह सतत प्रणाली बनानी चाहिए

भारत जैसे कम और मध्यम आय वाले देशों में खान-पाने के पैटर्न में तेजी से बदल हो रहे हैं। हाल ही में हुए व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (ष्टहहस्, 2019) के अनुसार कुछ दशकों से भारत में काफी आर्थिक विकास होने के बावजूद, भारत के तेरह से उन्नीस साल के बच्चे छोटे, पतले, ज़्यादा वजन वाले या मोटे हैं और 80त्न से ज़्यादा 'हिंडन हंगर' से पीड़ित हैं, जो कि आयरन, फोलेट, जिंक, विटामिन्, विटामिन क्च12 और विटामिन ष्ठ जैसे एक या एक से ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होती है। इसके अल्पकालिक/दीर्घकालिक या यहाँ तक कि कई पीढ़ियों पर दिखाई देने वाले दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं, जो कि उस भारत के लिए खतरा साबित हो सकती है जिसकी कल्पना हमने की हैं। कोविड-19 ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। कुपोषण हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे बीमार होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। यही नहीं, बुरी मैटाबॉलिक हेल्थ (जैसे कि मोटापा और मधुमेह) का खराब कोविड-19 नतीजों से काफी गहरा संबंध है। मौजूदा महामारी ने स्वास्थ्य, पोषण सेवाओं और स्थानीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करके रख दिया है, जिस वजह से खाद्य असुरक्षा से जुड़ी समस्याएँ बढ़ रही हैं। इससे भारत को अपने पोषण परिणामों में किए गए सुधार से मिलने वाले फायदे पर भी मुसीबत के बादल घिर आए हैं।

अपने खान-पान और कृषि प्रणालियों को फिर से नया रूप देना

पर्यावरणविद लगातार हमारी कृषि-जैव विविधता में हो रही कमी, प्राकृतिक संसाधनों बढ़ता दोहन, जलवायु परिवर्तन और उनका इंसान की सेहत पर पड़ने वाले असर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं (सेमिनार- जून 2020 का जस्टिस ऑन आवर प्लेट)। कोविड-19 के मौजूदा माहौल में इन सब के एक दूसरे से जुड़े होने के औचित्य के साथ-साथ देश भर के लोगों की ज़िंदगी और आजीविका पर पड़ने वाला इसका प्रभाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

हालांकि सरकार इनके बीच के संबंध को स्वीकार करती है, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सबसे पहले, हमारी विकास योजना के एक हिस्से के रूप में इन तीन तत्वों को एक साथ लाना ज़रूरी है। कृषि, पोषण और स्वास्थ्य। विशेषज्ञों ने लंबे समय तक नीति निर्माण में 'खाद्य प्रणाली' के प्रस्ताव की ओर बढ़ने के फायदों पर ज़ोर दिया है। ये बहु-क्षेत्रीय प्रस्ताव, खाद्य मूल्य श्रृंखला और व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण के संदर्भ में विभिन्न तत्वों के बीच संवाद, संबंधों और अंतर-निर्भरता पर आधारित है। ये सोच असल में हमारी संस्कृति में बहुत पहले से समाई हुई है; देसी आदिवासी समुदाय, उनके भोजन की आदतें और स्थानीय वातावरण के साथ ताल-मेल बैठाकर जीवन
जीने जैसे कई सबक सिखाता है।

दूसरा, लोगों के आस-पास किफायती दामों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं या नहीं यह पक्का करने के लिए स्वास्थ्य और पोषण के साथ कृषि का एकीकरण बेहद ज़रूरी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (स्वड्डष्ठ) द्वारा भारतीय पोषण कृषि कोष का विकास, हमारे द्वारा लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों और उनके स्रोत को समझने की सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। ऐसी कई किस्मों की स्वदेशी फसल हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं। साथ ही, कई कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल है। उपभोग के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उत्पादन प्रणाली में वापस लाना और स्थानीय श्रृंखलाओं का निर्माण करना बेहद ज़रूरी है।

स्वच्छ भारत, मिशन इंद्रधनुष और पोषण अभियान जैसे कार्यक्रमों के साथ सरकार पोषण पर असर डालने वाले बुनियादी मुद्दों को दूर करने के साथ-साथ व्यवहार में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर काम कर रही है। हालांकि, जिला स्तर पर स्थानीय ज़रूरतों और खाने की आदतों के हिसाब से नीति लागू करना बेहद ज़रूरी है; जो कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मौजूदा हालात में, ऐसा करने की बहुत कम गुंजाइश है कि कार्यक्रम और विभाग, संरचना में काम करना जारी रखें। पोषण मिशन को इस पर ध्यान देने और इस पर काम करने की ज़रूरत है।

प्रकृति के फायदों के परे देखना और सेहत और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध और पोषण पर इसके प्रभाव को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और परिस्थिति की बहुत हद तक सेहत के परिणामों को तय कर रहे हैं और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मौजूदा महामारी हमारे लिए इन मुद्दों पर काम करने, गियर शिफ्ट करने, विकासित करने, सही कृषि और खाद्य प्रणालियों और संवेदनशील पोषण कृषि-खाद्य श्रृंखलाओं को लेकर कदम उठाने का एक बेहतरीन मौका है। साथ ही, ये हमारे लिए यह सुनिश्चित करने का मौका है कि हम जो भोजन खाते हैं वह केवल सुरक्षित नहीं ही है बल्कि पौष्टिक होने के साथ-साथ सभी को उपलब्ध भी है। इस मुश्किल समय में प्रकृति हमारी सबसे बड़ी रक्षक हो सकती है।

मेरी रसोई मेरा औषधालय

रसोई मे ईस्तेमाल होने वाले मसालों के प्रकार व नाम

कई प्रकार के मसालों का उत्पादन करता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के इन मसालों का वर्तमान उत्पादन लगभग चार अरब यू एस डॉलर मूल्य के लगभग 32 लाख टन है और विश्व मसाला उत्पादन में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारण - उष्णकटिबन्ध क्षेत्र से उपोष्ण कटिबन्ध तथा शीतोष्ण क्षेत्र तक - लगभग सभी तरह के मसालों का बढिया उत्पादन भारत में होता है। वास्तव मंत भारत के लगभग सभी राज्यों व संघ-शासित क्षेत्रों में कोई-न-कोई मसाला उत्पन्न होता है।

भारतीय मसाले भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय जलवायु मसालों के लिए अच्छी है और भारत अन्तराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के साथ सूचीबद्ध 109 में से 75 प्रकार के मसालों का उत्पादन करता है।प्राचीन और मध्यकालीन युगों में भी भारतीय मसालों ने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय मसालों का इतिहास रोम, चीन आदि की प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार की एक ल6बी कहानी बताता है। केरल, पंजाब, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्य बढ़ते मसालों के केंद्र हैं। निर्यात के अलावा, इन मसालों का उपयोग देश में खाद्य पदार्थों के स्वाद के लिए और दवाओं, दवा, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और कई अन्य उद्योगों में भी किया जा रहा है। भारतीय मसालों का उपयोग सूखे बीज, पत्तियों, फूलों, छाल, जड़ों, फलों के रूप में किया जाता है और कुछ मसालों को पीसकर पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है।

- **बीज के प्रकार के मसाले:** कुछ सामान्य बीज जो मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वे हैं अजवाईन, अनारदाना, सौंफ, धनिया, जीरा, भारतीय दाल, सौंफ, मेथी, सरसों, खसखस या पोस्ता, आदि।
- **पत्ती के प्रकार के मसाले:** आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ मसाले जो प4ी की श्रेणी में आते हैं, वे हैं- तुलसी, लॉरेल लीव्स, तेजपात, करी लीव्स, पेपरमिंट लीव्स, पुदीना, पार्सले, सेज, सेवरी, रोज़मेरी लीव्स और अन्य।
- **फूल / फलों के प्रकार के मसाल:** कुछ सामान्य फूल जो मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वे हैं रोज़, केपर, रोडोडेंड्रोन, जुनिपर, कोकम, गदा और जायफल, वेनिला, आदि।
- **मूल प्रकार के मसाले:** मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जड़ें हैं : गंगंगल, लहसुन, अदरक, प्याज, मीठा झंडा, घोड़ा मूली, स्टोन लीक, लवेज, शालोट और हल्दी।
- **अन्य मसाले :** कुछ मसाले बीज, फल आदि की किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मसालों के परिवार से संबंधित हैं, जैसे काली मिर्च, लॉन्ग पेपर, चबिका, लौंग, अमचुर, हींग, करपूर, एरोवरोट और अन्य।

- अजवायन
- अमचूर
- अंबाकड़ी
- अजीनोमोटो
- अदरक
- अनारदाना
- इमली
- इलायची बड़ी
- इलायची छोटी
- करीपत्ता
- कसूरी मेथी
- काली मिर्च
- कलौंजी
- केसर
- खसखस
- गरम मसाला
- गोल मिर्च
- चीनी
- चाय की पत्ती
- चाट मसाला
- जीरा
- जावित्री
- जायफल
- तेल
- तिल
- दालचीनी
- धनिया
- नमक समुद्री सफ़ेद
- नमक काला
- नमक सेंधा
- नारियल
- तेजपात
- पुदीना
- फूलमखाने
- मिर्च लाल
- मिर्च हरी
- मिर्च सफ़ेद
- मिर्च काली
- मेथीदाना
- राई
- लौंग
- सोंठ
- सौंफ
- शाहजीरा
- हल्दी
- हरड़
- हींग

हल्दी

हल्दी (हरिद्रा) गुणों का खजाना है। हल्दी कन्द है जिसे बड़ी आसानी से घर पर उगाया जा सकता है। इसका पौधा बहुवार्षिक होता है। यह गर्मी की फसल है लेकिन इसे तेज धूप पसंद नहीं है। हल्दी के पत्ते, तना और कंद सभी का प्रयोग खाने और औषधि बनाने में किया जाता है।

धनिया पाउडर

धनिया दाना से तैयार किए गये पाउडर का प्रयोग संपूर्ण भारत में होता है। यह करी, दालों, सूखी सब्जियों, और लगभग सभी अचारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुश्बू तेज होती है, और इसके स्थान पर किसी और मसाले का प्रयोग नही किया जा सकता है।

काली मिर्च

काली मिर्च का प्रयोग खाने में मसाले के जैसे और दवाइयों में सदियों से होता आ रहा है। काली मिर्च एक पौधे का फल है। इसके फल गुच्छों में उगते है। काली मिर्च का फल हरा होता है और पक जाने पर फल का रंग लाल हो जाता है और जब इसे तोड़कर सुखाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। काली मिर्च अन्दर से हल्की सफेद होती है।

कचरे के ढेर पर बैठे शहर

एनजीटी का कहना है कि ठोस अपशिष्ट कचरे का निस्तारण न होने के कारण अधिकतर शहर महामारी के कगार पर पहुंच गए हैं। भारत सरकार की नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के सर्वेक्षण के अनुसार, सत्तर का दशक शुरू होने के साथ ही औद्योगीकरण ने भारत के शांत मैदानों, झीलों, झरनों का परिदृश्य बदल दिया है, जहरीले भारी रासायनिक तत्त्वों से धरती के अंदर का जल निरंतर प्रभावित हो रहा है।

कचरे के ढेर और उनसे पनपते रोग मानव समाज, पेड़-पौधे और पशु-पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। घरों से प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े से हजारों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, जिनसे हम अनजान रहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पशु-पक्षियों की मृत्यु भी कचरा खाने से हो रही है। पर हमारी सामाजिक और औद्योगिक व्यवस्था में कचरे के प्रबंधन पर जोर कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के दस सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली भी शामिल है। यहां प्रतिदिन करीब सात हजार टन ठोस कचरा पैदा होता है, जिसके निस्तारण के लिए सरकार के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। सबसे मुख्य बात है कि घरों से निकलने वाले कचरे को फेंकने से पहले प्रारंभिक स्तर पर छंटाई कर दें, तो प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। बाकी का काम कचरा निस्तारण प्रक्रिया के तहत कूड़े को प्लांट में पुनर्चक्रित करके किया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश भर में प्रतिदिन लगभग 1.43 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसके निपटारे की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इसमें प्रतिदिन 25,940 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। वहीं, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2031 तक प्रतिदिन साढ़े चार लाख टन कचरे का उत्पादन होगा, जो 2050 तक 11.9 लाख टन प्रतिदिन तक पहुंच जाएगा।

अधिकतर अपशिष्टों में अत्यंत निष्क्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं, जो निस्तारण प्लांट में पृथक करने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। विश्लेषकों के अनुसार भारत में लगभग 3.2 लाख टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, और इसका साठ प्रतिशत से भी कम इकट्ठा किया जाता है, केवल पंद्रह प्रतिशत निस्तारित हो पाता है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्याओं के कारण ग्रीनहाउस गैसों का प्रभाव बढ़ा है, जबकि लैंडफिल के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

नेशनल इनवारमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार कचरे का प्रबंधन प्राथमिक स्तर पर होने से करीब पैंसठ फीसद समस्या समाप्त हो जाती है। गौरतलब है कि एनजीटी ने कूड़े के निस्तारण को लेकर जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार ठोस अपशिष्ट के कारण हेपेटाइटिस, हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस तथा कॉलरा जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। कचरे का ढेर एक आम बात बन गई है, जो पर्यावरण, नदी, तलाब और झीलों को प्रदूषित कर रहा है।

ठोस कचरा आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अवांछित या बेकार ठोस सामग्री है, जिसे वैज्ञानिक तीन रूपों में वर्गीकृत करते हैं। इसमें मूल आधार (घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा निर्माण या संस्थागत), सामग्री (जैविक, कांच, धातु, प्लास्टिक और कागज आदि), खतरनाक कारक (विषाक्त, गैर-विषैले, ज्वलनशील, रेडियोधर्मी तथा संक्रामक) आदि शामिल हैं। घरों से निकलने वाले कचरे में सब्जियों और दूसरे आर्गेनिक पदार्थों के अलावा लोहे के डिब्बे, कागज, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े जैसे गैर-ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, जो खुले स्थानों पर फेंक दिए जाते हैं। इनका सही ढंग से निष्पादन न होने से पर्यावरण गंदा होता है। दुर्गंध फैलने के अलावा इनमें कीटाणु भी पनपते हैं, जो विभिन्न रोगों के कारक होते हैं। ऐसे स्थानों पर मच्छर, मक्खियां और चूहे पनपते हैं। घर में, घर के बाहर या बस्तियों में पड़ा कचरा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए भयंकर दुष्परिणाम पैदा करता है। हमारे यहां खेतों से निकलने वाले कूड़े-कचरे को भी नदियों में डाल दिया जाता है। इससे खतरनाक रसायन तथा कीटनाशक पानी में पहुंच जाते हैं। तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक देशों में समय की मांग को देखते हुए प्रदूषण की समस्या को ताक पर रख दिया गया है। भारत भी इन देशों में शामिल है। हमारे यहां की जनता प्रदूषण से होने वाले खतरों को अनदेखा करती है। रासायनिक प्रदूषण के प्रभाव को पूरे देश में तेजी से अनुभव किया जा रहा है। यह पाया गया है कि गैर-औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में, औद्योगिक क्षेत्रों में तरह-तरह के कैंसर, विभिन्न त्वचा रोग, जन्मजात विकृतियां, आनुवांशिक असामनता भी लगतार बढ़ रही हैं। स्वाभाविक रूप से सांस लेने में तकलीफ, पाचन क्रिया की परेशानी और संक्रामक बीमारियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। शहरों में पेट से जुड़ी सामान्य बीमारियां पिछले दशकों में बेतहाशा बढ़ी हैं। एनजीटी का कहना है कि ठोस अपशिष्ट कचरे का निस्तारण न होने के कारण अधिकतर शहर महामारी के कगार पर पहुंच गए हैं। भारत सरकार की नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के सर्वेक्षण के अनुसार, सत्तर का दशक शुरू होने के साथ ही औद्योगीकरण ने भारत के शांत मैदानों, झीलों, झरनों का परिदृश्य बदल दिया है, जहरीले भारी रासायनिक तत्त्वों से धरती के अंदर का जल निरंतर प्रभावित हो रहा है। भारतीय परिदृश्य में आम व्यक्ति के लिए ठोस अपशिष्ट के लिए प्रबंधन कोई जरूरी मुद्दा नहीं है। साथ ही भारत में पहले से मौजूद तकनीक तथा विधियों पर ही पुराने ढर्रे से काम हो रहा है, अभी तक नई-नई तकनीकों, कानूनों तथा लोगों में जागरूकता को उस स्तर पर नहीं लाया जा सका है, जिसकी इस समय आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सेंटर फॉर अर्बन एंड रिजनल एक्सीलेंस (क्योर) ने दिल्ली में पूर्वी दिल्ली जल निगम बोर्ड के साथ मिल कर कूड़े के निस्तारण की समस्या का हल निकाला। निम्न मध्यवर्ग के बीच कूड़े की छंटाई कर इसका निस्तारण करने की प्रक्रिया पर काम शुरू किया गया। इस मॉडल की सफलता के बाद इस योजना का तेजी से विस्तार हुआ और कई इलाकों में पूर्वी दिल्ली जल निगम बोर्ड के साथ मिल क्योर ने इसे लागू किया। प्रारंभिक चरण में वार्ड स्तर पर कूड़े को अलग-अलग बांटा जाता है। इस योजना के तहत इलाके के ट्रीटमेंट प्लांट को उपयोगी बना कर पूरे इलाके को जीरो वेस्ट वार्ड में तब्दील किया गया।

भले ये प्रयोग छोटे लगते हों, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हैं, क्योंकि घर के थोड़े से कचरे में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, जो आगे चल कर पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। शहरों में कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था करना नगरपालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन पहले हमें खुद पर्यावरण के प्रति संवेदनशाल होना होगा। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि घर के कूड़े को खुद अलग करें, फिर निस्तारण के लिए आगे भेजें।

आसान नहीं है टीके की राह

टीका तैयार

करने में जुटा हर देश और हर संस्थान यह दावा कर रहा है कि उसका टीका दूसरे की तुलना में सस्ता और ज्यादा कारगर साबित होगा।

अपेक्षाकृत कमजोर जीवित विषाणु वाले सफल टीकों की संख्या कम है, क्योंकि उन्हें बनाना जटिल काम है। ऐसा इसलिए भी है कि क्योंकि यह वास्तव में परीक्षण और त्रुटि पर आधारित होता है। इसमें जीन में होने वाले बदलावों का पता नहीं चल पाता है। निष्क्रिय विषाणु के टीकों को तैयार करने में बहुत उच्च मानकों को पूरा करना पड़ता है। इसमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि टीकों में सभी विषाणु कमजोर या निष्क्रिय ही हों। इस वक्त दुनिया कोरोना के जिस मकडज़ाल में फंस गई है, उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि अब इसका इलाज सामने आए, कोई दवा या टीका विकसित हो। तभी दुनिया में इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। इस वक्त दुनिया के कई देश टीके की खोज में लगे हैं। कुछ ने बना लेने का दावा किया है तो कुछ देश परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। दुनिया भर के दर्जनों शोध समूह जिस अथक प्रयास में लगे हैं, वह जुए की किसी बाजी से कम नहीं है। टीका तैयार करने में जुटा हर देश और हर संस्थान यह दावा कर रहा है कि उसका टीका दूसरे की तुलना में सस्ता और ज्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्दी ही टीका बना लेना कोई आसान काम नहीं है। ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रेजेनिका के जिस टीके को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति पर उसी का दुष्प्रभाव सामने आने के बाद परीक्षण अब रोकना पड़ गया है।

महामारी के इन सात महीनों में एक सौ तीस से अधिक प्रयोगात्मक टीकों पर काम चलने की बात सामने आई है। हाल में न्यूयार्क टाइम्स ने पुष्टि की कि दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में कम से कम अट्ठासी टीकों पर इस समय नैदानिक परीक्षण से पहले का शोध चल रहा है, जिनमें से सड़सठ टीकों पर अगले साल (2021) के अंत तक चिकित्सकीय परीक्षण पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इस दौड़ में शामिल टीकों में से जो सबसे आगे नजर आ रहे हैं, वे सब एक ही जैव-चिकित्सीय सिद्धांत पर आधारित और निर्मित हैं, जिसमें एक प्रोटीन (स्पाइक प्रोटीन) है, जो प्राकृतिक रूप से कोरोनाविषाणु के ऊपरी कवच पर पाया जाता है। जब यह प्रोटीन शरीर के अंदर पहुंचेगा तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के संकेत देगी और अंतत- सैद्धांतिक रूप से इससे बनने वाला एंटीबॉडी कोरोनाविषाणु को नष्ट कर देगा। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं की चिंता यह है कि हमें एक ही तरह की रणनीति पर बहुत अधिक उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, वह भी ऐसी रणनीति जिसे अभी सफल साबित होना बाकी है। इसीलिए वाशिंगटन विश्वविद्यालय में विषाणु विज्ञानी डेविड वेस्लर का कहना है कि %अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में रखना बुद्धिमत्ता नहीं है'।

बीते मार्च में डॉ. वेस्लर और उनके सहयोगियों ने एक नैनो कण वाला टीका तैयार किया था, जिसमें हर एक नैनो कण पर स्पाइक प्रोटीन की नोक की साठ प्रतियां एक साथ जुड़ी थीं। इन नैनो कणों में

पूरी स्पाइक प्रोटीन शृंखला के बजाय उसका बाहर निकले हुए नुकीले हिस्से, जो कोरोनाविषाणु के मानव शरीर में घुसने के बाद हमारी कोशिकाओं से सबसे ज्यादा संपर्क में आता है, का इस्तेमाल किया गया है। यह एक बहुत मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। जब इन नैनो कणों को चूहों में प्रवेश कराया गया, तो उनमें कोरोनाविषाणु के खिलाफ बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया हुई। जब इन चूहों को कोरोनाविषाणु के संपर्क में लाया गया, तो इन चूहों में संक्रमण नहीं फैला और जांच में ये चूहे संक्रमण से सुरक्षित पाए गए। इस सफल परीक्षण के बाज दी डॉ. वेस्लर और उनके एक सहयोगी नील किंग द्वारा स्थापित कंपनी, आइकोसावैक्स, जल्द ही 'नैनोकण टीके' का परीक्षण शुरू करेगी। अमेरिकी सेना के वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक और 'स्पाइक-नोक नैनो कण' वाला टीका बनाया है, जिसका परीक्षण भी चल रहा है। कुछ अन्य कंपनियां और विश्वविद्यालय भी 'स्पाइक-नोक नैनो कण' वाले टीके पर काम कर रहे हैं। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी कई दूसरे अस्त्रों के साथ एक प्रतिरोधी हथियार है। टी-रक्त-कोशिकाएं भी उन्हीं में से एक हैं, जो विषाणु द्वारा संक्रमित की गई कोशिकाओं को खा जाती हैं। ब्राजील के साओ पाउलो के इंस्टीट्यूटो बुटानन की एक शोधकर्ता लुसियाना लेइट का कहना है कि 'हम अभी भी नहीं जानते हैं कि किस तरह की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण होगी।'

केवल एंटीबाडी प्रतिक्रिया प्रेरित करने वाले टीके लंबे समय में बेकार साबित हो सकते हैं। एक टीके का प्रभाव इससे भी तय होता है कि यह हमारे शरीर में किस रास्ते से भेजा जाता है। सभी टीके, जो चिकित्सकीय परीक्षण में हैं, मांसपेशियों में लगाए जाते हैं। इंफ्लूएंजा के सफलतम टीके (फ्लूमिस्ट) को नाक के रास्ते स्प्रे किया जाता है। यह प्रणाली कोरोनाविषाणु के खात्मे लिए इसलिए भी उचित है, क्योंकि कोरोना विषाणु वायु मार्ग से ही हमारे शरीर में आता है। नाक से स्प्रे के जरिए दिए जाने वाले टीकों में सबसे कल्पनाशील पहल न्यूयॉर्क की एक कंपनी कोडॉजेनिक्स की है। वह एक ऐसे टीके का परीक्षण कर रही है जिसमें कोरोनाविषाणु का सिंथेटिक संस्करण प्रयोग किया जा रहा है। दशकों से टीकों के निमार्ताओं ने चेचक और पीत-ज्वर जैसे रोगों के लिए कमजोर जीवित विषाणु का सफलता से प्रयोग किया है। परंपरागत रूप से, वैज्ञानिक कमजोर विषाणु को प्राप्त करने के लिए मुर्गियों या अन्य जानवर की कोशिकाओं में उनकी वंश-वृद्धि करते हैं। लेकिन ये विषाणु अभी भी मानव कोशिकाओं में घुस पाने में सक्षम होते हैं, हालांकि, उनका प्रजनन बहुत धीमा हो जाता है। परिणामस्वरूप, वे हमें बीमार नहीं कर पाते। इन कमजोर विषाणुओं की छोटी खुराक प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करती है। अपेक्षाकृत कमजोर जीवित विषाणु वाले सफल टीकों की संख्या कम है, क्योंकि उन्हें बनाना जटिल काम है। ऐसा इसलिए भी है कि क्योंकि यह वास्तव में परीक्षण और त्रुटि पर आधारित होता है। इसमें जीन में होने वाले बदलावों का पता नहीं चल पाता है।

निष्क्रिय विषाणु के टीकों को तैयार करने में बहुत उच्च मानकों को पूरा करना पड़ता है। इसमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि टीकों में सभी विषाणु कमजोर या निष्क्रिय ही हों। वाल्नेवा का टीका पहले ही उन मानकों को पूरा कर चुका है, लेकिन चीनी टीकों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए ब्रिटेन ने वाल्नेवा के टीके की छह करोड़ खुराक पहले ही से खरीद ली है। अगर ये टीके के शुरूआती स्तर पर भी कामयाब रहते हैं, तो अगली चुनौती इनकी भारी-भरकम वैश्विक मांग को पूरा करने की होगी।

कई पारंपरिक टीके बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जा सकते हैं, जिनका उपयोग सुरक्षित और प्रभावी ढंग से दशकों से हो रहा है। कोडॉजेनिक्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ अपने विषाणु वाले टीके के उत्पादन के लिए साझेदारी की है। यह कंपनी पहले से ही खसरा, रोटाविषाणु और इन्फ्लूएंजा के लिए जीवित-कमजोर विषाणु के टीकों की अरबों खुराक बनाती है। स्थापित कार्यप्रणाली का इस्तेमाल करने से टीके की लागत भी काफी कम बैठेगी, जिससे इसे गरीब देशों में वितरित करना आसान होगा।

इसके अलावा बैलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ता भी सस्ते टीके पर काम कर रहे हैं, जिसकी लागत दो डॉलर प्रति खुराक है। बैलर की टीम ने कोरोनोविषाणु %स्पाइक-नोक' बनाने के लिए खमीर को तैयार किया है। यह ठीक उसी तरह की विधि है जिससे 1980 से ही हेपेटाइटिस-बी का टीका बनाया गया था। भारतीय टीका निमार्ता बायोलॉजिकल-ई इसे बनाएगा और यह परीक्षणों के करीब है।

भले दुनिया को कोविड -19 से बचाव के लिए सस्ते और प्रभावी टीके मिल जाएं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आने वाली महामारियों की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जंगली जानवरों में छिपे बैठे अन्य कोरोनाविषाणु से कोविड-19 जैसी महामारी कभी भी प्रकट हो सकती है। कई कंपनियां, जिनमें चीन की अनहुइ जोइफी, फ्रांस की ओसिवैक्स और अमेरिका की वीबीआइ भी हैं, कोरोनविषाणु के टीके विकसित कर रही हैं और ये ऐसे विषाणु समूह से सुरक्षा देंगे, जिन्होंने मानव जाति को अब तक संक्रमित नहीं किया।

निष्क्रिय विषाणु के टीकों को तैयार करने में बहुत उच्च मानकों को पूरा करना पड़ता है। इसमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि टीकों में सभी विषाणु कमजोर या निष्क्रिय ही हों। वाल्नेवा का टीका पहले ही उन मानकों को पूरा कर चुका है, लेकिन चीनी टीकों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए ब्रिटेन ने वाल्नेवा के टीके की छह करोड़ खुराक पहले ही से खरीद ली है। अगर ये टीके के शुरूआती स्तर पर भी कामयाब रहते हैं, तो अगली चुनौती इनकी भारी-भरकम वैश्विक मांग को पूरा करने की होगी।

कई पारंपरिक टीके बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जा सकते हैं, जिनका उपयोग सुरक्षित और प्रभावी ढंग से दशकों से हो रहा है। कोडॉजेनिक्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ अपने विषाणु वाले टीके के उत्पादन के लिए साझेदारी की है।

काकुरो पहेली - 1867

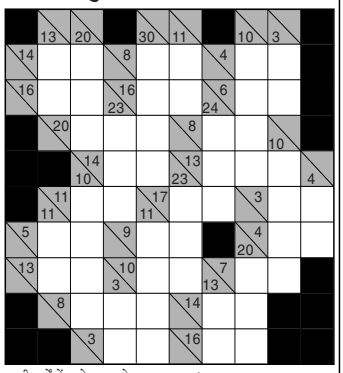

खाली वर्गों में 1 से 9 तक के अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खानी चाहिए.किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता.

उदाहरणतः

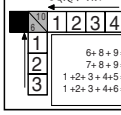

6+ 8 + 9 = 23
7+ 8 + 9 = 24
1 +2+ 3 + 4+5 = 15
1 +2+ 3 + 4+6 = 16

काकुरो - 1866 का हल

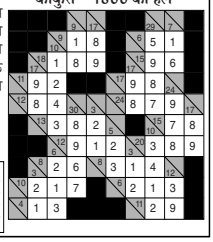

लॉफिंग ज़ोन

बड़े लंबे अरसे बाद दो पुराने पड़ोसी दोस्त मिले। एक-दूसरे का हालचाल पूछने पर मालूम हुआ कि दोनों शादी कर चुके हैं।

पहला उत्सुकतावश बोला- कैसी है तुम्हारी पत्नी?

दूसरे ने चहककर बताया- मेरी पत्नी का क्या कहना यार! वो तो स्वर्ग की अप्सरा है अप्सरा...!

पहला मायूस होकर दबे स्वर में बोला- खुशकिस्मत हो भाई! मेरी तो अभी जिंदा है....।

□ □ □

बहुत दिनों के बाद पुराने मित्रों का मिलन हुआ। रमेश ने पूछा- तुम्हारी उस प्रेमिका का क्या हुआ, जिसके तुम बहुत बड़े आशिक हुआ करते थे, उस जमाने में।

नरेश- कुछ खास नहीं! उसकी माँग इतनी बड़ी थी कि मुझे उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा।

रमेश- अच्छा! लेकिन तुम्हारी प्रेमिका की माँग क्या थी?

नरेश- तुमसे शादी करने की।

□ □ □

एक बच्चा तालाब में डूब रहा था। सभी देख रहे थे। किसी में हिम्मत न थी कि बच्चो को बचा लाए। तभी एक साहब ने छलांग लगा दी और बच्चो को बचा लिया। दर्शकों में से एक बोला - बडी हिम्मत की आपने ।

वह व्यक्ति बोला - हिम्मत की ऐसी-तैसी, पहले यह बताओ, मुझे धक्का किसने दिया था ?

फिल्म वर्ग पहेली- 1867

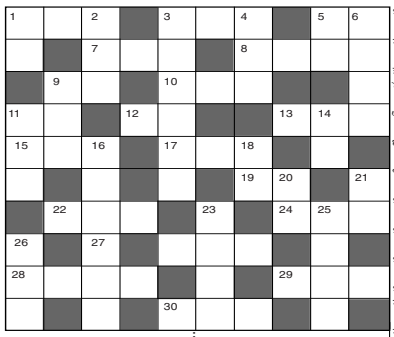

ऊपर से नीचे:-

१. 'कैसे कटे दिन कैसे' गीत वाली राजेश, गोविंदा, जूही की फिल्म-२
२. अमिताभ, जयाप्रदा की 'मंजिलें अपनी जगह हैं' गीत वाली फिल्म-३
३. फिल्म 'तेरे नाम' में नायक कौन था-४,२
४. ऋषि, चंकी, नीलम की 'देखा जो हुस्न आपका' गीत वाली फिल्म-३
५. काहे कोयल शोर, मचाये' गीत वाली राजकपूर, नर्गिस की फिल्म-२
६. जीतेंद्र, लीना चंदावरकार की 'तूने तूने ओ सनम' गीत वाली फिल्म-४
९. 'है मुबारक आज का' गीत वाली मिथुन चक्रवर्ती, रति की फिल्म-३
११. संजय दत्त, अनिता की 'तुझा तुझा तक तक तुझा' गीत वाली फिल्म-३
१४. 'हम तुम को निगाहो' गीत वाली सलमान, अरबाज, शिल्पा की फिल्म-२
१६. राजकपूर, वहीदा रहमान की 'सजन रे झूठ मत बोलो' गीत वाली फिल्म-३,३
१८. फिल्म 'मिस ४२०' में नायिका कौन थी-२
२०. सनी देओल, सलमान, करिश्मा, तब्बू की 'तू धरती पे चाहे जहाँ' गीत वाली फिल्म-२
२१. 'फूल ये कहाँ से' गीत वाली जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया की फिल्म-२
२३. अजय देवगन, अमीषा पटेल की 'प्यार तो होता है प्यार' गीत वाली फिल्म-४
२५. 'मेरे अंगने में तुम्हारा' गीत वाली अमिताभ, जीनत अमान की फिल्म-४
२६. अरविंद स्वामी, प्रभुदेवा, काजोल की 'एक बगिया में रहती हैं' गीत वाली फिल्म-३

बायें से दायें:-

१. 'ये तारा वो तारा' गीत वाली आशुतोष गोवारीकर की फिल्म-३
३. 'तुम्हें अपना बनाने की' गीत वाली संजयदत्त, पूजा भट्ट की फिल्म-३
५. राजकपूर, नर्गिस की 'ये शाम की तनहाइयाँ' गीत वाली फिल्म-२
७. 'चलती है पुरवाई' गीत वाली जतिन ग्रेवाल, नेहा की फिल्म-३
८. ऋषिकपूर, जयाप्रदा की 'रामजी की निरली सवारी' गीत वाली फिल्म-४
९. 'मैं शायर तो नहीं' गीत वाली ऋषिकपूर, डिम्पल की फिल्म-२
१०. राजेश खन्ना, शर्मिला की 'कन्हैया कन्हैया तुझे' गीत वाली फिल्म-३
११. 'बंदा ये बिंदास है' गीत वाली अमिताभ, रवीना, नंदिता की फिल्म-२
१२. अमिताभ, जीनत की 'ये मेरा दिल यार का दीवाना' गीत वाली फिल्म-२
१३. 'दिन सारा गुजारा' गीत वाली शम्मी कपूर, सायरा की फिल्म-३
१५. राजेंद्रकुमार, वहीदा की 'ये मौसम भीगा भीगा है' गीत वाली फिल्म-४
१७. 'वो शाम कुछ अजीब थी' गीत वाली राजेश खन्ना, वहीदा की फिल्म-३
१९. आमिर, जूही, ममता की 'धीरे धीरे आप मेरे' गीत वाली फिल्म-२
२२. फिल्म 'रिफ्यूजी' में अभिषेक के साथ नायिका कौन थी-३
२४. अक्षयकुमार, करीना की 'दिल ले गया परदेसी' गीत वाली फिल्म-३
२७. 'बहारों फूल बरसाओ' गीत वाली राजेंद्रकुमार, वैजयंती की फिल्म-३
२८. किशोरकुमार की 'एक चतुर नार करके सिंगार' गीत वाली फिल्म-४
२९. 'फिर वही चांद वही गम' गीत वाली देवआनंद, नूतन की फिल्म-३
३०. डिनो, विपाशा की 'जब दिल चुराये कोई' गीत वाली फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली- 1866

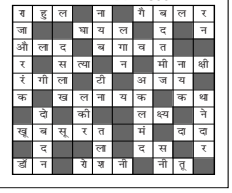

साधु और चूहे की कहानी

बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु मंदिर में रहा करता था। उनकी दिनचर्या रोजाना प्रभु की भक्ति कराना और आने-जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना थी। गांव वाले भी जब भी मंदिर आते, तो साधु को कुछ न कुछ दान में दे जाते थे। इसलिए, साधु को भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं होती थी। रोज भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना छींके में रखकर छत से टांग देता था। समय ऐसे ही आराम से निकल रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब-सी घटना होने लगी थी। वह जो खाना छींके में रखता था, गायब हो जाता था। साधु ने परेशान होकर इस बारे में पता लगाने का निर्णय किया। उसने रात को दरवाजे के पीछे से छिपकर देखा कि एक छोटा-सा चूहा उसका भोजन निकालकर ले जाता है। दूसरे दिन उन्होंने छींके को और ऊपर कर दिया, ताकि चूहा उस तक न पहुंच सके, लेकिन यह उपाय भी काम नहीं आया। उन्होंने देखा की चूहा और ऊंची छलांग लगाकर छींके पर चढ़ जाता और भोजन निकाल लेता था। अब साधु चूहे से परेशान रहने लगा था। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षुक आया। उसने साधु को परेशान देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो साधु ने भिक्षुक को पूरा किस्सा सुना दिया। भिक्षुक ने साधु से कहा कि सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा उछलने की शक्ति कहां से आती है।

उसी रात भिक्षुक और साधु दोनों ने मिलकर पता लगाना चाहा कि आखिर चूहा भोजन कहां ले जाता है। दोनों ने चुपके से चूहे का पीछा किया और देखा कि मंदिर के पीछे चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ है। चूहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा, तो देखा कि चूहे के बिल में खाने-पीने के सामान का बहुत बड़ा भण्डार है। तब भिक्षुक ने कहा कि इसी वजह से ही चूहे में इतना ऊपर उछलने की शक्ति आती है। उन्होंने उस सामग्री को निकाल लिया और गरीबों में बांटा दिया। जब चूहा वापस आया, तो उसने वहां पर सब कुछ खाली पाया, तो उसका पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने-पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। यह सोचकर उसने रात को छींके के पास जाकर छलांग लगाई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नहीं पहुंच पाया और साधु ने उसे वहां से भगा दिय

खोजी एनसीआर पत्रिका

में विज्ञापनों एवं अपने सुझावों के लिए संपर्क करें

Phone N0 01268-277129,9416254840, 9518002332

E-Mail khojincr@gmail.com

Online News

के लिए क्लिक करें

www.khojincr.com

R.K. Jain

Infra Projects Pvt. Ltd.

Head Office : Firozpur Jhirka, Opp. Mini Sector-8

Rakesh Jain
Director